दैनिक हिन्दी अख़बार

सच बेधड़क

www.sachbedhadak.com | twitter.com/sachbedhadak | facebook.com/sachbedhadak
YouTube: youtube.com/@sachbedhadak | Instagram: instagram.com/sach_bedhadak

वर्ष: 3 | अंक: 212 — जयपुर, गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 | आषाढ़, शुक्ल पक्ष- पंचमी , विसं 2081 — पृष्ठ: 10 | मूल्य: 2.00

बजट भाषण
शुरू- 11 बजे

कुल समय
2 घंटे 51 मिनट

शेर व कविता पर तालियां और दाद

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पेश किया भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट

युवाओं की बात... हर साल 1 लाख नौकरियों की सौगात

■ विकास, युवा, स्वास्थ्य, किसान व वर्ग महिला पर फोकस, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे

■ वित्त मंत्री दिया कुमारी का पहले पूर्ण बजट भाषण में झलका आत्मविश्वास ■ शुरुआत निदा फाजली के शेर से और अंत अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से

15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी

छात्रों को मुफ्त में मिलेगा टैबलेट व इंटरनेट

जयपुर। *"सफर में धूप तो होगी... जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में... तुम भी निकल सको तो चलो।"* मशहूर शायर निदा फाजली की गजल के इस मुखड़े के साथ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जब बजट भाषण का पहला पैरा शुरू किया तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट वाह-वाह की दाद से गूंज उठा।

दिया कुमारी ने अपने 2 घंटे 51 मिनट के पहले बजट भाषण में प्रदेश में विकास के विजन की तस्वीर पेश की। खासकर युवा वर्ग, रोजगार, शिक्षा, किसान वर्ग, पर्यटन के साथ आगामी 5 साल का खाका जनता के सामने रखा। हर साल 1 लाख नौकरियां, शहरी विकास व 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणाएं खास रही। उन्होंने अंत में पूर्व पीएम वाजपेयी की कविता पढ़कर खूब सराहना पाई।

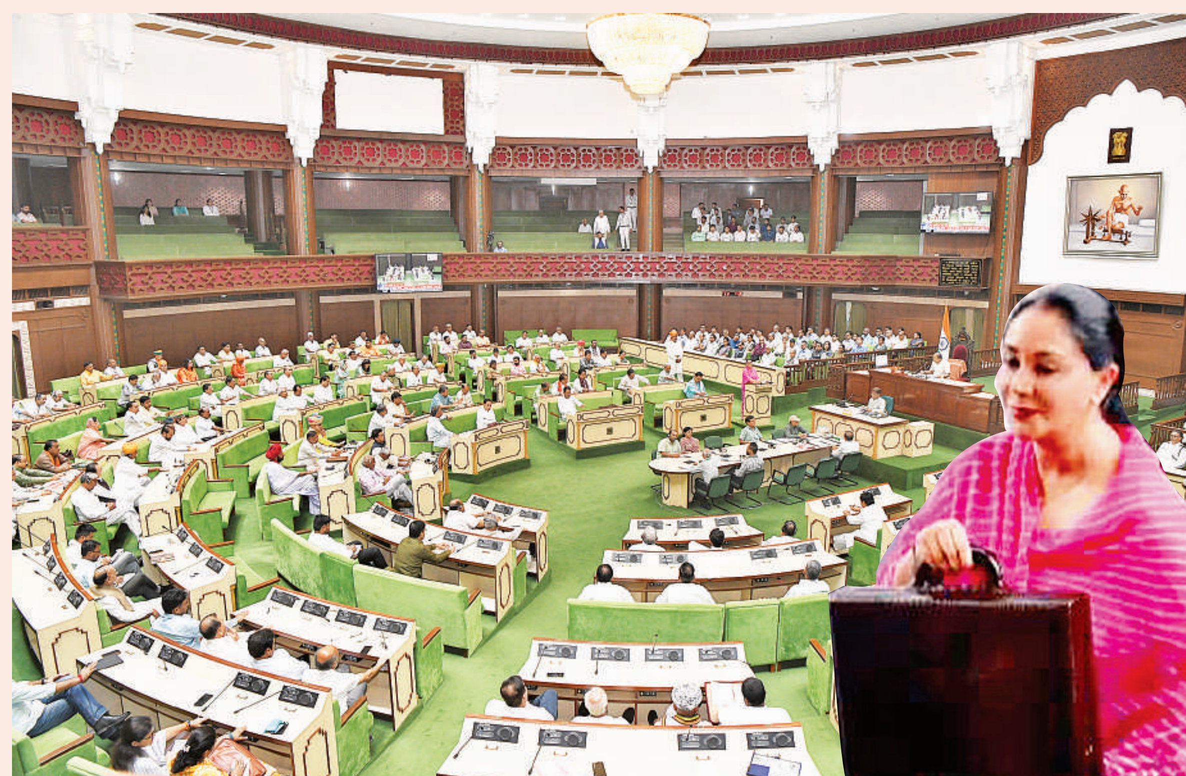

बजट में प्रदेश सरकार का विजन : वन-टू-वन

स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़

भजनलाल सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा रोजगार सृजन को लेकर दिया। हर साल 1 लाख नौकरियों की घोषणा के साथ सरकार अगले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा की। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.50 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा, इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

शहरी विकास

शहरों में विकास के नए आयाम विकसित करने को लेकर सरकार ने विशेष फोकस रखा है। ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज करने के लिए 150 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए की लागत से कमजोर लोगों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

जिला स्तर पर खुलेंगे वर्किंग वुमन हॉस्टल

महिला व बाल विकास पर विशेष फोकस करते हुए सरकार ने लखपति दीदी योजना के प्रसार को महत्व दिया है। प्रदेश में करीब 15 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। वहीं, आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी। जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। बालिकाओं को पुलिस-सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा।

अब 'कुलपति' कहलाएंगे 'कुलगुरु'-

प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। विवि के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।

मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए

प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सभी अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा। खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा।

क्या सस्ता, एक नजर....

ये हुए सस्ते :

- सीएनजी और 50 लाख रुपए तक की कीमत वाले फ्लैट की रजिस्ट्री सस्ती
- राज्य में सीएनजी-पीएनजी पर लगने वाले वैट को 14.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान
- फ्लैट की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6 से घटाकर 5 फीसदी किया

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नही

बजट में भजनलाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर लग रहे वैट की दर को कम करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा अटकी। इनकी कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल पर अधिक वैट वसूल किया जाता है।

कर्मचारियों को तोहफा

- संविदा कर्मचारियों को अब दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट दिया जाएगा
- आरजीएचएस में अब सरकारी कर्मचारी माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे।
- कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन दी जाएगी, 1 अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा।
- पेंशनर्स अब 50 हजार रुपए तक का इलाज करा सकेंगे।

भजन सरकार के दस संकल्प

- प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना
- पानी, बिजली, सड़का का विकास
- सुनियोजित शहरी विकास
- किसानों का सशक्तीकरण
- औद्योगिक विकास
- 'विरासत भी, विकास भी' की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
- पर्यावरण संरक्षण
- सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
- वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

राजधानी जयपुर को तोहफा : दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनेगा

- राजधानी जयपुर में 9 जगह फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड बनेंगे।
- सीएम भजनलाल व दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्रों के लिए 165 करोड़ के खर्च से सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाएगा।
- शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होंगी। -आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलों पर रोप-वे बनाए जाएंगे।
- एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित होगा।
- दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा।
- जनक मार्ग से शुरू होकर खातीपुरा मोड़ से क्वींस रोड होते हुए पुरानी चुंगी पर अंडरपास बनेगा।
- झारखंड मोड़ से सिरसी रोड पर गौतम मार्ग तक एलीवेटेड रोड की डीपीआर बनाई जाएगी।
- सिरसी रोड पर राणा कुम्भा मार्ग से होते हुए सिरसी मोड़ तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई जाएगी।
- नाड़ी का फाटक पर 86.89 करोड़ की लागत से 4 लेन का आरओबी।
- सीतावाली फाटक से बैनाड़ फाटक के बीच 14.37 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज।
- जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक पर 95 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज।
- सालीग्रामपुरा फाटक पर 86 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे।

■ बजट के विस्तृत समाचार एवं विश्लेषण भीतर पेज 2,3,4,5 और 6 पर भी देखें।

खाटूधाम के लिए 100 करोड़ ₹ देने का ऐलान... बनेगा कॉरिडोर

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन के लिहाज से कई बड़े ऐलान किए। इसके तहत प्रदेश के 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया।

उन्होंने राज्य सरकार नई पर्यटन नीति भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बजट में जो एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि खाटू श्याम जी धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा किया कि काशी विश्वनाथ के तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा।

600 मंदिरों में उत्सव के लिए ₹13 करोड़

बजट में वित्त मंत्री ने चार बड़े त्योहारों पर राज्य के 600 मंदिरों में साज सज्जा व आरती के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। बजट में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि दीपावली, होली, शिवरात्रि और रामनवमी जैसे त्योहारों पर प्रदेश के 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा और आरती के कार्यक्रम किए जाएंगे।

सीएम प्रेस से रू-ब-रू, बोले...

जनता की आशाओं को पूरा करने का प्रयास

बेधड़क| जयपुर

प्रदेश में सरकार का पहला बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम कहा कि हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से जनता की आशा-आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारे बजट में विजन है, 2047 का राजस्थान कैसा हो? इसको लेकर विशेष फोकस किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 10 साल में हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी का विजन हर बजट में सामने आया है। प्रदेश के बजट में भी हमारा विजन साफ है। उन्होंने कहा, इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। किसान, युवा और महिलाओं समेत सभी वर्गों को बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। समाज के हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो, इसके लिए आगामी योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

जनता की सेवा में नहीं छोड़ेंगे कोर कसर

जनता ने हमें बहुमत दिया है, हम जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से योजना में 500 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 6 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। दिल्ली-जयपुर के बीच औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। एक साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। बजट में युवाओं की भागीदारी पर फोकस रखा गया है, वहीं प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए विशेष पैकेज दिए है।

पक्ष- विपक्ष

प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाने वाला बजट: गजेंद्र सिंह

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के बजट को विकास के नए पथ पर ले जाने वाला बजट बताया है। शेखावत ने बुधवार को बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सर्वसमावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी को शुभकमानाएं देते हुए कहा कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास के नए पथ पर लेकर जाएगी। इस बजट के माध्यम से राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बनेगा।

लोक कल्याणकारी बजट: मेघवाल

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में पेश बजट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी को बधाई देते हुए कहा कि बजट विकसित राजस्थान की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर मसौदे के रूप में लोक कल्याणकारी एवं सर्व समावेशी है।

पूरी तरह दिशाहीन बजट: डोटासरा

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश बजट को पूर्णतया दिशाहीन बताया है। डोटासरा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए एमएसपी, कृषि लागत कम करने, आमजन को महंगाई से राहत देने एवं गरीब को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज देने का कोई प्रयास नहीं दिखा है।

महंगाई, बेरोजगारी कम करने के कोई ठोस कदम नहीं : पायलट

भाजपा सरकार से जनता को उम्मीद थी कि लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन प्रस्तुत बजट से प्रदेश की जनता को विशेकर मध्यम वर्ग, किसान, युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है। राजस्थान की बेरोजगारी दर को कम करने का सरकार द्वारा बजट में कोई रोड़मैप प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार को बेरोजगारी को कम करने के लिए अगले पांच सालों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प मात्र लेने के स्थान पर इसके लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

सभी सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा

25 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर

परंपरागत और अन्य स्रोतों से बिजली उत्पादन पर रहेगा फोकस

बेधड़क | जयपुर

उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर विभिन्न सुधरात्मक घोषणाओं के साथ नई परियोजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 साल में 6% बिजली की खपत बढ़ जाएगी। ऐसे में अक्षय ऊर्जा सहित अन्य ऊर्जा उत्पादन विकल्प पर सरकार का फोकस रहेगा।

इसके साथ ही दो नए सोलर पार्क विकसित होंगे। सरकार बिजली की छीजत रोकने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में है। सरकार 2030 तक की बिजली आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए 2 लाख 25 हजार करोड़ की लागत से तंत्र को मजबूत करने जा रही है। बजट में वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के हर घर और हर खेत को बिजली देने के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मार्च में लिग्नाइट और कोयला आधारित इकाइयां लगाने के लिए एमओयू हो चुका है। कुसुम योजना के तहत 3500 मेगावट की बिजली उत्पादन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गए हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए लैंड पॉलिसी लागू की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली की छीजत रोकने के लिए एनर्जी लिकेज रिफॉर्म के चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दो साल में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

- प्रदेश में बिजली से वंचित 2 लाख 8 हजार घरों को दो साल में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में नए छोटे व बड़े बिजली घर बनेंगे।
- रिन्यूएबल एनर्जी के तहत 50 हजार मेगावाट की क्षमता के निजी क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने के लिए पूगल, छतरगढ़ और बुढ़ाना जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित होंगे।
- राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए नीति बनेगी। इसमें पंप स्टोरेज का सामवेश होगा। इसमें बारां, भरतपुर व अन्य जिलों में पंप स्टोरेज के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन पर जोर होगा।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनेगा, जिसमें दो मेगावाट सौर प्लांट लगेगा। इसमें 40 फीसदी अनुदान होगा।
- प्रदेश के 765 केवी के 6,400 केवी के 7, 220 केवी के 15 और 132 केवी के 40 बिजली घरों से संबंधित लाइनों के विस्तार व निर्माण कार्य होगा।
- प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा।
- बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

उद्योग

- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी. टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई. इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा। इसके साथ ही बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी।
- पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे. साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी।
- ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी।

एक साल में 15 लाख लखपति दीदी बनाएगी भजनलाल सरकार

बजट में सरकार ने महिला सशक्तीकरण को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। खास तौर से सरकार ग्रामीण महिलाओं को संबल देने के उद्देश्य से केंद्र की घोषित लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ा रही है। पहले एक साल में पांच लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना था, अब इसे 15 लाख महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ सहित अन्य अपराध रोकने के लिए पुलिस की निर्भया स्क्वाड को विकसित करते हुए पांच सौ कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स बनाने की घोषणा की है। प्रथम चरण में 250 यूनिट उतारी जाएंगी।

महिला सशक्तीकरण की प्रमुख घोषणाएं

- पांच सालों में 2 लाख नए Self Help Groups (SHGs) के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 हजार समूहों को revolving fund एवं 15 हजार समूहों को आजीविका संवर्धन राशि (Community Investment Fund) उपलब्ध करवाते हुए 40 हजार नवीन SHGs गठित किया जाना प्रस्तावित है।
- Self Help Groups (SHGs) की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है।
- जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए Hostel एवं Paying Guest सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
- बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस में जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा

- गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा, इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे. वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25 हजार का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा।
- पाक विस्थापितों को प्रति परिवार एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी।
- बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा।
- एससी-एसटी के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- EWS के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज मुहैया कराया। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया।

किसानों और पशुपालकों की भरी झोली

किसानों को दिन में सिंचाई के लिए मिलेगा पानी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कृषि बजट के तहत किसानों और पशु पालकों को कई सौगातें दी। वित्त मंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए राजस्थान इरिगेशन वॉटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा के साथ ही सिंचाई और जल संचय के लिए 50 हजार करोड़ से अधिक के कार्य कराए जाने की घोषणा की। साथ ही प्रदेश में राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 650 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे।

प्रदेश के किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन के लंबित आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त कर एक लाख 45 हजार कनेक्शन जारी करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के तहत रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत 30 हजार करोड़ से अधिक के कार्य होंगे। यमुना जल संबंधी कार्य के तहत 577 एमसीएफटी पानी के लिए हरियाणा सरकार से एमओयू किया गया है। इसके तहत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्सन कार्य के लिए 60 करोड़ की डीपीआर तैयार की जाएगी।

इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के तहत 1430 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, कृषि ही मानव जीवन का आधार है। जल संचय के लिए 50 हजार करोड़ से अधिक के काम होंगे। रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना होगी। 30 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यमुना जल के संबंध में 60 करोड़ की लागत से DPR बनेगी।

प्रमुख घोषणाएं

- राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
- नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की गई।
- किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनेगा. गोवर्धन परियोजना की शुरुआत होगी।
- 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।
- दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना कर दिया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया।
- समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
- प्रदेश में 500 नए FPO खोले जाएंगे। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा। ऊंट पालकों को 20 हजार रुपए अनुदान मिलेगा।

15000 करोड़ के खर्च से 25 लाख घरों में 'नल से जल' पहुंचाने का वादा

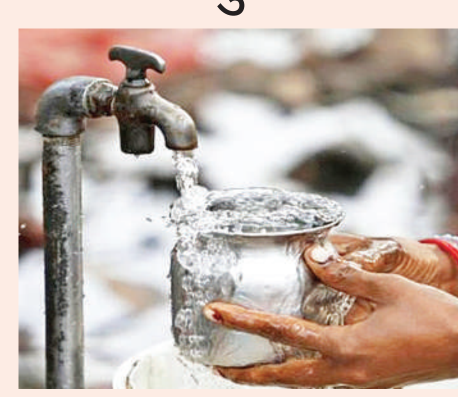

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में ऐलान किया कि 15000 करोड़ के खर्च से राज्य में 25 लाख घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। यह कार्य जलजीवन मिशन के तहत होगा। विधानसभा में वित्त मंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि विगत सरकार ने इस मिशन के कामों में उदासीनता बरती थी, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता है, जिसके चलते लाखों घर इससे वंचित रह गए थे। इस काम को हम तेजी से पूरा करेंगे। अमृत 2.0 के तहत समयबद्ध क्रियान्वयन पिछली सरकार ने नहीं किया था।

हम इस काम को पूरा करेंगे। ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 'संकल्प पत्र की 45 फीसदी घोषणाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित हो सकती है।

पेयजल की बड़ी घोषणाएं

- अमृत 2.0 के तहत 183 शहरों व कस्बों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 5180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि से दो साल में काम पूरा होंगे।
- प्रदेश के 32 शहरों के जलस्त्रोतों के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 127 करोड़
- अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रिजर्वायर व नसीराबाद से नौसर कोटडा तक पाइपलाइन प्रस्तावित है।
- टोडारायसिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा व अलीगढ़ टोंक के लिए शहरी पेयजल के तहत 50 करोड़ की लागत से उच्च जलाशय बनेंगे।
- प्रदेश के शहरों में पेयजल पाइपलाइन कार्य होंगे। विधानसभा क्षेत्र में बीस-बीस हैंडपंप लंगेगे और दस-दस ट्यूबवेल खोदे जाएंगे।
- दूषित पानी को रिसाइकल करने के लिए हैंप तकनीक से सीवरेज प्लांट लगेंगे।

1500 डॉक्टर्स की भर्ती, आयुष्मान आरोग्य योजना होगी लागू

हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 10 हजार

बेधड़क | जयपुर

उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हेल्थ सेक्टर के लिए 27,660 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो राज्य के कुल बजट का 8.2% है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की जाएगी। इसमें कैंसर, आईपीडी और डे केयर को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की जाएगी।

इसके अलावा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाने की घोषणा भी गई। डिप्टी सीएम ने बजट में ऐलान किया कि सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब सरकार की तरफ से 10 हजार रुपए मिलेंगे। बजट में 1500 नए डॉक्टर और

4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई। चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा। निष्क्रिय 10 ट्रॉमा सेंटर को संचालित किया जाएगा और 6 नाइट ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए राशि का रेड डिजीज फंड बनाया जाएगा। अस्पतालों के लिए मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगा। इसके तहत 15 हजार करोड़ के काम करवाए जाएंगे। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होगी। प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा।

एक नजर में बजट

- 27 हजार करोड़ का रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया। यह पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है।
- 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद होंगे सृजित।
- राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की होगी शुरुआत।
- प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर बनेगा ई-हेल्थ रिकॉर्ड ।
- आयुष्मान भारत योजना की तरह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना शुरू होगी।
- आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जुड़ेगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े जाएंगे।
- छोटे स्थानों पर निजी अस्पतालों के इंपैनलमेंट के नियमों में रियायत दी जाएगी।

> खुल्यो खजानों राज को, बजट है मूसळाधार
> वादा घणा ई राज का, करज्यो पूरा सरकार।

बजट पेश होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस से हुए रू-ब-रू

जनता ने हमें बहुमत दिया, हम विकास में नहीं छोड़ेंगे कमी

बेधड़क | जयपुर

प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और एसीएस अखिल अरोड़ा भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि जनता ने हमे बहुमत दिया है।

हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि हमने बजट के साथ विजन भी पेश किया है। बजट में सरकार का विजन भी होना चाहिए। हमने इस बात की कोशिश की है कि सरकार का विजन दिखे। हमने बजट में बताया कि 2047 में प्रदेश का विकास कैसा होगा? 2047 में राजस्थान कैसा होगा? इसका विजन पेश किया है।

हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा करेगी सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बिजली पानी के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ-साथ किसान युवा, महिला और औद्योगिक विकास का ध्यान रखा है। हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा करेगी। हमने चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। इस साल एक लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने किसानों के उत्थान के लिए काम करने का वादा किया था, उस वादे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया, जिसे पूरा किया। ऊर्जा के क्षेत्र में दस साल में आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम अग्रणी होंगे। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे।

धार्मिक और विरासत पर्यटन को विकसित करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। धार्मिक, ग्रामीण या विरासत पर्यटन को विकसित करेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। सुशासन हमारी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था भी प्राथमिकता के रूप में ला रहे है। राज्य पशु ऊंट के लिए भी अनुदान बढ़ाया है। किसान के जीवन में पशु पालन बड़ा काम है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। हम आठ करोड़ जनता के विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट को रखा है।

पक्ष- विपक्ष

अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान

गजेंद्र सिंह खींवसर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में बड़ा कदम है। विकसित भारत को लेकर बजट में दिए गए 10 संकल्प विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए 8.26 प्रतिशत बजट प्रावधान रखना यह इंगित करता है कि राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र को लेकर बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, उद्योग, कृषि, आधारभूत ढांचे, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो न केवल प्रदेश के विकास को गति देंगी, बल्कि विकसित राजस्थान के हमारे संकल्प को भी साकार करेंगी।

काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा

अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री

'हमारी सरकार ने मिशन-2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। आशा थी कि हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार कम से कम राजस्थान की बेहतरी के लिए इस मिशन को ध्यान में रखकर काम करेगी और विकास की बेहतरीन योजनाएं लाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है। बजट से न जनता को राहत मिली है और ना ही कोई विकास का रोडमैप बन रहा है। पिछले 10 साल से जैसा केंद्र सरकार का बजट नीरस एवं दिशाहीन होता है। यह दिखाता है कि ये सरकार काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है।

पिंकसिटी में बनेंगे 9 जगह फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड

राजधानी में बिछेगा सड़कों का जाल

बेधड़क | जयपुर

बजट में इस बार जयपुर में 9 स्थानों पर फ्लाईओवर, आरयूबी, एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्रों में 165 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसमें नई सड़क बनाने के अलावा पुरानी सड़कों का नवीनीकरण भी होगा। वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी के निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर के विभिन्न वार्डो में 75 करोड़ रुपए में सड़कों का निर्माण होगा, जबकि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र मानसरोवर-सांगानेर एरिया में 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में इस बार सरकार ने जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किले पर रोप-वे भी बनाए जाएंगे। एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेट ऑफ दि आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, वहीं दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा।

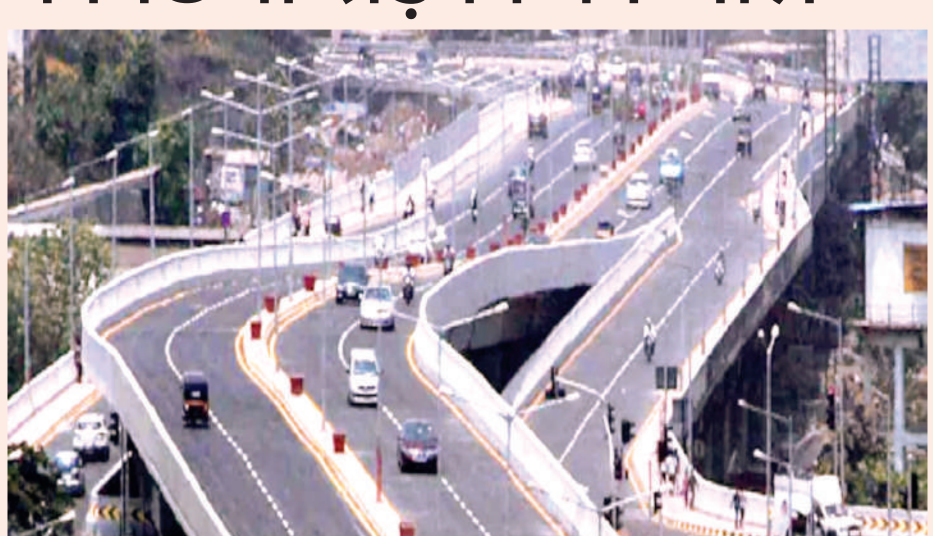

यहां बनेंगे फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड

जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक पर 95 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज। सालीग्रामपुरा फाटक पर 86 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज, 65 करोड़ रुपए की लागत से सहकार मार्ग, इमली फाटक पर फ्लाइओवर, नाड़ी का फाटक पर 86.89 करोड़ की लागत से 4 लेन का आरओबी, जनक मार्ग से शुरू होकर खातीपुरा मोड़ से क्वींस रोड होते हुए पुरानी चुंगी पर अंडरपास बनाते हुए झारखंड मोड़ से सिरसी रोड पर गौतम मार्ग तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई जाएगी। सिरसी रोड पर राणा कुंभा मार्ग से होते हुए सिरसी मोड़ तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई जाएगी। सीतावाली फाटक से बैनाड़ फाटक के बीच 14.37 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी), गोपालपुरा बाइपास रिद्धि-सिद्धि तिराहे पर 72 करोड़ की लागत से फ्लाओवर, महेंद्रा सेज पर 200 और 250 फीट रोड के इंटरसेक्शन पर 90 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर, पृथ्वीराज नगर दक्षिण योजना में वंदे भारत सड़क पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर 98 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर, जयपुर में अंबेडकर सर्किल से ओटीएस चौराहा और यहां से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करना. जयपुर में सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक 170 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड, जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर बनाने का काम होगा।

आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलो पर रोप-वे की होगी शुरुआत

बिछेगा सड़कों का जाल, झालाना में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

बेधड़क | जयपुर

जयपुर के विद्याधर नगर एरिया में 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइनें बिछाई जाएगी। मानसरोवर-सांगानेर क्षेत्र में 90 करोड की लागत से सडकों का उन्नयन। कालाडेरा-प्रतापपुरा-जालसू-जाहोता-जयरामपुरा में 40 करोड़ रुपए की लागत से 25 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनाई जाएगी। महापुरा से खटवाड़ा तक 3.5 किमी लंबाई में सड़क का निर्माण होगा। फागी रोड से टोंक रोड को कनेक्ट करने के लिए सड़क 30 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। जयपुर में सेक्टर रोड निर्माण के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

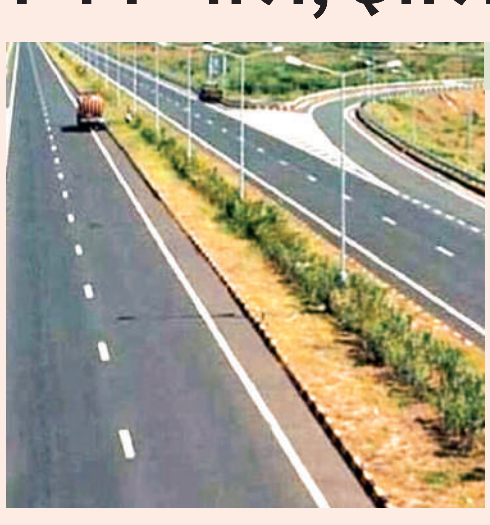

ये भी मिला राजधानी को

- झालाना में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।
- ट्रैफिक की समस्या का समाधान के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस वॉलंटियर्स दिए जाएंगे।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेट ऑफ दि आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा।
- जयपुर के परकोटे और हैरिटेज बिल्डिंग के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान बनाकर काम शुरू करवाया जाएगा।
- आरयूएचएस जयपुर में नया ट्रोमा सेंटर बनेगा. जयपुर में अटल इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिसमें इनोवेशन से संबंधित लोगों को प्लेटफार्म दिया जाएगा।
- आमेर में लाइट एंड शो का बेहतर तरीके से करवाया जाएगा. दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा।
- आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलो पर रोप-वे शुरू करवाया जाएगा, इसके लिए डीपीआर बनाई जाएगी।
- जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल कैपेसिटी को 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 70 लाख करने और नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी।
- जयपुर मेट्रो रेल को सेंट्रल के सहयोग से बजट दिया जाएगा, ताकि मौजूदा प्रोजेक्ट्स का काम करवाया जा सके।
- जयपुर के पर्यटन स्थलों पर आईटी से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। जयपुर में पौधारोपण और पार्क के विकास कार्य के लिए अलग से बजट दिया जाएगा।

बजट : झलकियां...

- बजट विफक्रेस के साथ सदन पहुंची वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विक्ट्री साइन दिखाया। इनके साथ आए विधायकों के चेहरे खिले दिखे। इस दौरान उनके साथ हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी रहे।
- लड्डू खाए और खिलखिलाएं: बजट पूरा होने के बाद सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम को लड्डू खिलाकर बधाई दी। इस दौरान किसी बात को लेकर माहौल खुशनुमा हो गया तथा सभी मौजूद नेता खिलखिलाएं।
- दिया कुमारी की प्रतिक्रिया पर खिलखिलायां सदन: बजट पेश करने के दौरान विपक्ष के बार बार व्यवधान करने पर दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तंज कसा। इस दौरान पूरा सदन खिलखिलाया।
- वाजपेयी की रचना पढ़ी: ... बजट के दौरान दिया कुमारी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता -....
  टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर
  सुनाया तो एक बारगी पूरे सदन में शांति छा गई।
- दिया कुमारी की कविता पर थपथपाई मेज: लेकर अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य नित करें हम मानव कल्याण, दे सहारा करें असहाय वृद्ध जन का सम्मान, दे नारी को प्रोत्साहन।
  है भार युवा कंधों पर, आओ कंधे उनके मजबूत बनाएं। आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ाए।
  कविता की इन पक्तियों को सुन पूरे सदन ने मेज थपथपाई।
- विपक्ष का सन्नाटा, मंत्री का तंज
  बजट भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत से बजट पारित करने के लिए सबसे पहले सत्ता पक्ष के विधायकों से हां पक्ष को लेकर स्वर मांगा। इस पर ध्वनि मत से सत्ता पक्ष के विधायकों ने हां कहा। इसके बाद उन्होंने बजट पर विपक्ष को लेकर पूछा। इस पर विपक्ष के नेता तो शांत रहे। इस पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने खड़े होकर कहा- सन्नाटा।
- विपक्ष के हंगामें पर स्पीकर ने कहा - आपको भी बहुत कुछ मिलेगा: बजट के दौरान जब दीया कुमारी पेज पलटकर आगे बढ़ाने लगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- बहुत लंबी सूची है। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत भाजपा विधायकों ने मेज थपथपाकर समर्थन किया। इसके बाद भी दीया पन्ने पलटती रहीं। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा- अभी आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मिल रहा है। फिर दीया कुमारी ने कहा ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद विपक्ष के सदस्य चुप हुए।
- अंबेडकर व विवेकानंद को किया याद: वित्त मंत्री ने औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर व स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। उन्होंने कहा- आर्थिक उन्नति और सामाजिक उत्थान की पूंजी औद्योगीकरण में है। स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए दीया कुमारी ने कहा- बहादुर, स्पष्टवादी, साफ दिल वाला, साहसी और महत्वाकांक्षी युवा ही एकमात्र नींव है। जिस पर भविष्य के राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।
- राजेंद्र राठौड़ की कमी खल रही है....: वित्त मंत्री की ओर से महिला सुरक्षा की बजट घोषणा के दौरान डोटासरा ने कहा कि कुछ भी कहो, आज राजेंद्र राठौड़ की कमी खल रही है। इसे सुन दीया कुमारी भी मुस्कुराने लगी। इस पर स्पीकर ने डोटासरा से कहा- आप उनकी कमी को पूरा कर रहे हो क्या?
- स्पीकर ने धारीवाल से कहा- आप कुछ तो गरिमा रखो: बजट के दौरान स्पीकर ने कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को टोकते हुए कहा- आप कुछ तो गरिमा रखो। आप बीमार हो बैठो, इधर भी यही करते थे, उधर भी यही कर रहे हो। इस पर कांग्रेसी विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया।

देस्यां घणी ई नौकरी, भरती करस्यां चार लाख
मेहनत करल्यो टाबरो, लागैं सूपना कै पांख

राजस्थान रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाएगा

सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे

जयपुर। अपने पहले बजट में भजनलाल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया है। सड़कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर की कई अहम घोषणाएं करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 5 साल में 53 हजार किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क तैयार करने का एलान किया है। साथ ही रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाने की घोषणा की। प्रदेश में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे भी बनाए जाएंगे।

नई सड़क परियोजनाओं पर खर्च होंगे 60 हजार करोड़

प्रदेश में 60000 करोड़ खर्च करके नई सड़क परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगे इसमें बाईपास सड़कें और स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे। इसमें 9000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के रिपेयर रेलवे और ब्रिज अंडर ब्रिज सड़क और पूलों के काम करवाएं जाएंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर, कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-कोटपुतली 290 किमी के बनाए जाएंगे। पांच सालों में 13 हजार किमी लंबाई की सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे। स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।

जिला उत्थान योजना में 500 करोड़ का प्रावधान

- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रत्येक जिले की प्राथमिक समस्याओं के निस्तारण और आवश्यकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर और अन्य चयनित शहरी निकायों में वाई-फाई इनेबल्ड लाइब्रेरी और को वर्किंग स्टेशंस की स्थापना पर 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के नगरी निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाए जाने की दृष्टिगत 2024-25 और 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपए की लागत से फायर ब्रिग्रेड उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण और 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस पर लगभग 650 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- कचरा संग्रहण व ट्रांसपोर्टेशन तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आईटी तकनीक जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। साथ ही नगर निगम में संचालित इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशंस को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जाएगा। इस पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा, सामुदायिक कार्य, अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी कार्य 1300 करोड़ की लागत से करवाए जाएंगे। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के बाजारों और पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से भी बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्थापित कराए जाने प्रस्तावित है। पहले चरण में नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में 67 टॉयलेट कंपलेक्स बनाए जाएंगे, इस पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कमजोर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं की जाएंगी विकसित

- 1300 करोड़ रुपए की लागत से कमजोर लोगों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। पहले फेज में नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में टॉयलेट कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो को केंद्र के साथ जॉइंट वेंचर में बदला जाएगा।
- जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनल की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी। बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाआों के लिए फ्री जमीन देने की घोषणा की गई। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा।

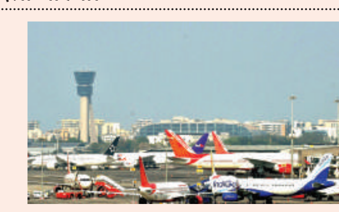

सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे, रोडवेज में 1650 भर्तियां होंगी

शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल पर आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जाएंगी। साथ ही ई बसों के सुगम संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 800 बसें किराए पर ली जाएंगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे। रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा की गई है। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड रोड का प्रावधान भी किया जाएगा।

एसी बसों में अब यात्रा हो जाएगी महंगी, प्रति किमी. 10 पैसे बढ़ा किराया

रोडवेज की एसी बसों में अब यात्रा महंगी हो जाएगी। जयपुर से दिल्ली जाने पर 28 रुपए तक ज्यादा देने होंगे, 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए। राज्य की भजनलाल सरकार ने बजट से एक दिन पहले राजस्थान रोडवेज की वातानुकूलित (एसी) बसों के किराए में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को एसी बस में 28 रुपए तक किराया ज्यादा देना होगा। किराया प्रति किलोमीटर 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक (यातायात) की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक वर्तमान में एक यात्री का किराया 1.55 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया था, जिसे बढ़ाकर अब 1.65 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया निर्धारित किया गया है। इस 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी से जयपुर से दिल्ली की दूरी जो करीब 280 किलोमीटर है उससे किराये में 28 रुपए तक बढ़ोतरी हो गई। बढ़ा हुआ किराया 10 जुलाई की रात से लागू हो गया।

'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' पॉलिसी लाएंगे, हर साल का बजट 10 करोड़

'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फोर लोकल के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे। ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।

5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य कराए जाएंगे

नई पर्यटन नीति बनाई जाएगी, पर्यटन विकास बोर्ड भी बनेगा

बेधड़क | जयपुर

राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र के रोजगार से जुड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। इसके तहत पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। सरकार इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाए जाएंगे जाएगा। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलिजियस, इको टूरिज्म विकास के काम किए जाएंगे। 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे। पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकासकरने के लिए राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा। जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारकों को जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा। इसके लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। झीलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम करेगा। इसके साथ ही जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा। आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोप वे बनेगा। इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा। पांडुपोल, अलवर और त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर में ईवी व्हीकल चलेंगे। वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा। आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोप वे बनेगा।

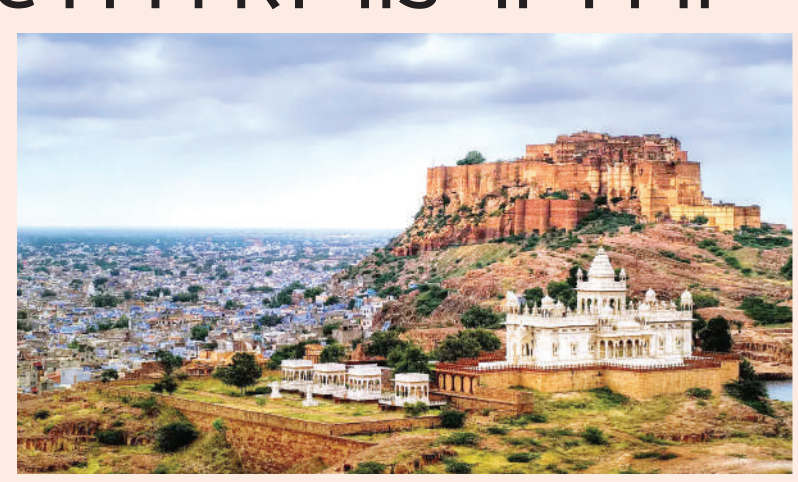

एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्सटाइल और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी लाएंगे

प्रदेश में बनेगा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव भी होगा

बेधड़क | जयपुर

बजट में राजस्थान में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना किए जाने की घोषणा की जाएगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। टेक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा। सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी। इसके साथ ही बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी।

कारोबारी बोले-डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी

भजन सरकार के पहले पूर्ण बजट को लेकर कारोबारियों का कहना है कि यह विकासपरक है। इसमें काफी घोषणाएं की गई हैं, जिससे प्रदेश के डेवलपमेंट में काफी सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री ने कारोबारियों को एक बड़ी राहत देते हुए एक्सपोर्ट के लिए अलग से नीति बनाने की बात कही है, जो राजस्थान के लिए काफी कारगर साबित होगी। राजस्थान की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, स्टोन आदि राजस्थान से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट को लेकर एक अलग पॉलिसी बनेगी तो काफी राहत मिलेगी। कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने अपने बजट में इंडस्ट्री को लेकर एक अलग से पॉलिसी बनाने की बात कही है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस पॉलिसी में कारोबारियों की भागीदारी भी सरकार को करनी चाहिए, ताकि व्यापारियों की बात भी सरकार तक पहुंच सके। कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने अपने इस बजट में नई टूरिज्म में पॉलिसी की बात भी कही है, जिससे राजस्थान के व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।

एक्सपर्ट व्यू: राजस्थान की राजधानी को देश की नंबर -1 सिटी बनाने वाला बजट

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में प्रदेश की राजधानी जयपुर के सौंदर्यीकरण के लिए कई घोषणाएं की गईं। इसमें नई एलीवेटेड रोड्स के निर्माण के अलावा शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की भी घोषणा की गई। बजट में जयपुर के परकोटे और हेरिटेज बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ का प्लान बनाकर काम शुरू करवाने की घोषणा की गई। साथ ही आमेर में लाइट एंड शो को अविस्मरणीय बनाए जाने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री दियाकुमारी ने दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाए जाने की भी बात कही। जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलो पर रोप-वे शुरू करवाया जाएगा, इसके लिए डीपीआर बनाए जाने की घोषणा की गई। जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल कैपेसिटी को 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 70 लाख करने और नया टर्मिनल बनाए जाने की घोषणा मील का पत्थर साबित होगी।

-सीए ऋषि अग्रवाल, बजट एक्सपर्ट

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की बजट में युवाओं के लिए रोजगार सहित अहम घोषणाएं

रोजगार पर पूरा फोकस, लाएंगे युवा और खेल नीति

बेधड़क, जयपुर। स्वामी विवेकानंद के कथन..."बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है, जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है" को दोहराते हुए उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में युवा विकास एवं कल्याण संबंधी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। 'युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना' प्राथमिकता है। बजट घोषणा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई अहम घोषणा युवाओं को लेकर की। इसमें सबसे बड़ी तो पांच साल में चार लाख नौकरी देने की है। इस वित्त वर्ष में 70 हजार से अधिक नौकरियों देने की घोषणा को बढ़ाकर 1 लाख किए जाने की मंजूरी दी है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएगे। वहीं युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से 'युवा नीति-2024' लाये जाने की घोषणा की। नवीन नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किए जाने की घोषणा की। वहीं 'खेल नीति-2024' के अलावा राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की घोषणा की। वहीं स्कूली और उच्च शिक्षा को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की, जिसमें नए कॉलेज खोलने से लेकर सरकारी स्कूलों के भवनों का जीर्णोद्धार भी शामिल है। वहीं, स्कूल के मेधावी छात्रों को 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ टैबलेट देने की घोषणा भी की गई है।

अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियां होंगी। इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी भर्ती होगी। प्रदेश में पुलिस में 5500 और 1500 डॉक्टरों और 400 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित होंगे। रोडवेज में भी 1650 कर्मचारियों की भर्ती होंगी

इनका कहना है:

प्रदेश का बेहतरीन और ऐतिहासिक बजट है। बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया है। ये बजट डबल इंजन सरकार के उद्देश्य, विकसित और सशक्त राजस्थान के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। खास कर युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी को बधाई।

मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार

बजट में विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की रिपेयर के लिए 50 करोड रुपए, SC ST एवं TSP Funds की राशि बढ़ाने कर 1500 करोड रुपए, दिव्यांग जनों के लिए 2000 स्कूटी वितरण मील का पत्थर साबित होगी।

अविनाश गहलोत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

युवाओं में बढ़ते सुसाइड को लेकर कठोर कदम की जरूरत है। इसकी बजट में घोषणा होनी चाहिए थी। उच्च शिक्षा में भर्ती रोस्टर प्लान की घोषणा होती तो अच्छा रहता। वहीं युवा नीति 2024 व स्टेट स्किल पॉलिसी से पर्सनेलिटी डेवलपमेंट होगा। राजस्थान यूथ आइकॉन से युवाओं में जागृति आएगी। खेल में नवाचार को ध्यान में रखा गया है। कुलपति को अब "कुलगुरू" काफी सहरानीय है।

कुश शर्मा, यूनिवर्सिटी विद्यार्थी

सरकार के पहले पूर्ण बजट में राज्य के लाखों शिक्षकों को तबादला नीति के ड्राफ्ट नहीं पेश हुआ। उप प्राचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती सहित वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित शिक्षकों की अन्य मांगों पूरी नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग में संवर्गों के हिसाब से कोई घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर राज्य बजट मिला जुला है। इस बजट से शिक्षकों को मायूसी मिली है।

मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा, राजस्थान

हायर एजुकेशन क्षेत्र के लिए

- गुरू-शिष्य सम्बन्ध की परम्परा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'कुलगुरू' की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
- दो वर्षों में 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसके तहत नाचना पोखरण जैसलमेर में नया आईटीआई, जबकि बांदीकुई (दौसा), फागी (दूदू), वल्लभगढ़ (उदयपुर), निवाई (टोंक), मारवाड़ जंक्शन (पाली), गुढ़ामालानी (बाड़मेर) में नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शुरू होंगे। साथ ही आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नए ट्रेड, ब्रांच लाए जाएंगे।
- प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई. इन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

- गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को दोबारा स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न महाविद्यालय की स्थापना.
- संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन और विस्तार के लिए भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण करवाए जाएंगे. इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए

- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई।
- 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए विषय प्रारंभ करने की घोषणा।
- विद्यालय में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से चार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास और 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।
- स्कूलों में क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और टॉयलेट के निर्माण के लिए 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- 750 विद्यालयों के भवन मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
- प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के काम करवाए जाएंगे।

- राज्य में सभी वर्गों के राजकीय और अनुदानित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्रों का मैस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा।
- खेलकूद आवासीय विद्यालय के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए करना प्रस्तावित।
- राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टि से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33000 विद्यार्थियों को टैबलेट विथ 3 ईयर इंटरनेट कनेक्टिविटी निशुल्क दिए जाने की घोषणा।
- रेवासा सीकर में संचालित वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को देय मानदेय को 8000 से बढ़ाकर 15000 रुपए किया जाएगा।

खेल क्षेत्र के लिए

- 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी।
- संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी।
- खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी।
- पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी।
- खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे।
- राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित होगा।

1500 चिकित्सकों और 4 हजार नर्सिंगकर्मियों की होगी भर्ती

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक हजार 500 चिकित्सकों तथा 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पदों का सृजन किया जायेगा। साथ ही, RajMES के अन्तर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को adopt किया जाना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए संभाग पर बालिका सैनिक स्कूल

बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस में जाने के लिए आवश्यक सुविधायें देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किये जाने की घोषणा की।

पुलिस में 5500 नये पदों का सृजन और नई बटालियन

प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस में 5 हजार 500 नये पदों के सृजन किए जाएगें। इसके अन्तर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सिक्यूरिटी पुलिस फोर्स का गठन होगा। आरएसी के अन्तर्गत पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवायी जाएगी।

तीन इंजीनियरिंग बनेंगे अब आरआईटी

युवाओं को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर, अजमेर, बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में उन्नत किया जाएगा। इस पर कुल 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेशभर में संभाग स्तर पर आदर्श आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। भरतपुर समेत प्रदेश के प्रत्येक संभाग पर 50-50 करोड़ की लागत से स्पोटर्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ताकि खेल प्रतिभाओं को निखारा का सके। साथ ही प्रत्येक जिले में खेल अकादमी भी स्थापित की जाएगी। संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल खिला जाएगा। ताकि संभाग की बालिकाएं यहां शिक्षा ग्रहण कर रक्षा क्षेत्र में करियर बना सकें। आमजन को सभी विभागों की सेवा व समस्या के समाधान लिए एक ही स्थान पर सभी विभागों के अधिकारियों संपर्क करने के लिए एक ही स्थान पर इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स व सर्विस सेंटर यानी कर्मशिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। इससे आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा।

संविदाकर्मियों को मिलेंगे एक साल में दो बार इंक्रीमेंट

बेधड़क | जयपुर

शासन-प्रशासन के सुचारू संचालन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने कर्मचारियों की महत्ती भूमिका है। इसके लिए प्रदेश में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों के लिए राज्य कर्मचारियों की भांति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष दो तिथियां 1 जुलाई एवं 1 जनवरी निर्धारित है। यानि साल में दो इंक्रीमेट का मौका मिलेगा। Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को एक हजार 200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा। 30 जून, 2023 (तीस जून वो हजार तेईस) को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2023 से दिये जाने की घोषणा की है। इसी तरह भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून (तीस जून) को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह लाभ दिया जाएगा। Central Government Health Scheme की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत Medical लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरूष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब 3 दिन किया दूध दिया जाएगा

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख (छत्तीस लाख) बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाये जाने घोषणा हुई। इसके लिए के लिए क्रय किये जाने वाले milk powder पर 200 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किये जायेंगे। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए गैस की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में, प्रथम चरण में इस वर्ष 2 हजार केन्द्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

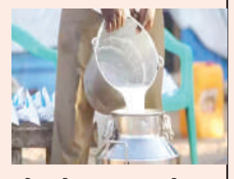

चाकसू में खेल स्टेडियम और छात्रावास पुनर्निर्माण के लिए तीन करोड़ रु. मिलेंगे

बेधड़क | चाकसू

भजनलाल सरकार का बुधवार को पहला पूर्ण बजट पेश हो गया। इसमें चाकसू में खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा के साथ हीं कोटखावदा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय स्वीकृत हुआ है।

माधोराजपुरा में बिजली विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय की स्वीकृति मिली है। विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र घोषणा एवं छात्रावास पुनर्निर्माण के लिए लगभग तीन करोड रूपये मिलेंगे। एक आयुष्मान मॉडल सीएससी मय मोर्चरी निर्माण की भी घोषणा हुई हैं। चाकसू छात्रावास भी मरम्मद का कार्य भी किया जाएगा।

यह है क्षेत्रवासियों की प्रतिक्रिया

चाकसू कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल मीणा ने कहा कि इस बजट में चाकसू विधानसभा को कुछ नहीं मिला। लोगों को उम्मीद थी कि तीन महत्वपूर्ण मांगे कोटखावदा में उपखंड कार्यालय, गर्ल्स कॉलेज एवं चाकसू तक मेट्रो का विस्तार होगा लेकिन इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। लोगों को निराशा हाथ लगी है। गुर्जर समाज कोटखावदा अध्यक्ष श्रवण गुर्जर ने बजट को लेकर कहा कि कोटखावदा क्षेत्र की महत्वपूर्ण दो सड़कों सहित पीएचइडी विभाग का एईएन कार्यालय खुलने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही खाटू श्याम कॉरिडोर एवं देवनारायण मंदिर आसींद को लेकर जो घोषणाएं की गई है उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर भाजपाइयों ने सरकार का आभार जताया हैं।

"विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो मांगे रखी गई थी, उनमें से अधिकतर पूरी हो गई है। कुछ चीजें जो रह गई है वह पूरक बजट में मिल जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

रामावतार बैरवा,
चाकसू विधायक

खेल: बजट ने जगाई कायाकल्प की उम्मीद

गजानन्द शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान का बजट पेश हो गया है। इस बार वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक अहम प्रस्ताव रखा है और यह प्रस्ताव है हर संभाग में खेल स्कूल खोलने का। राजस्थान देश का एक बड़ा प्रदेश है और सैन्य पृष्ठभूमि वाला राज्य है, लेकिन प्रदेश को अभी तक खेलों में जो खास पहचान या बड़ा नाम मिला है तो वह सेना की वजह से ही मिला है। इसमें चाहे कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ को ओलंपिक खेलों में शूटिंग में मिला रजत पदक हो या ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले राज्य के अन्य खिलाड़ी हों, उनमें ज्यादातर सेना की वजह से ही यह मुकाम हासिल कर सके क्योंकि वे सेना के सदस्य थे। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन आजादी के सात दशक के बाद भी राजस्थान खेलों में एक ताकत नहीं बन पाया। कारण प्रदेश में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव और खेल संस्कृति का विकास न होना, लेकिन इस बार राज्य की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे और खेल संस्कृति के विकास की उम्मीद जगाता है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में कुछ अहम घोषणाएं की हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस बार प्रदेश का खेल मंत्रालय एक खिलाड़ी व सेना के पूर्व सदस्य कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ के पास है। फिर भी सरकार की ओर से की गई घोषणाएं प्रदेश में खेलों के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जगाता है। बजट में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के अलावा संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। विश्वविद्यालय जहां कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकता है, वहीं स्पोर्ट्स कॉलेज खेल संस्कृति के विकास में सहायक बन सकती हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक जिला-एक खेल योजना लागू करने की घोषणा की है। इससे क्षेत्र विशेष में प्रचलित खेलों को मुख्यधारा में लाने व नवोदित प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ

ही वित्त मंत्री ने मिशन ओलंपिक की घोषणा की है। इसके तहत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार की ये घोषणाएं उम्मीद जगाती हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के स्पोर्ट्स पावर बनकर उभर सकता है।

हालांकि इसके लिए बहुत ही लग्न, धैर्य और समर्पण के साथ काम करने की जरूरत है और इसके लिए पूर्व क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ जैसे समर्पित खेल विशेषज्ञों व खिलाड़ियों की जरूरत होगी। जिनका सपना हो कि राजस्थान खेल ताकत बने और वे एक जुनून के साथ उसे साकार करना चाहें। यह विडंबना ही कही जाएगी कि एक विशाल प्रदेश होने और सैन्य पृष्ठभूमि वाले युवाओं की बहुलता होने के बावजूद राजस्थान अभी तक खुद की खेलों में वैसी पहचान नहीं बना पाया जैसे कि पड़ोसी हरियाणा या पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर ने बनाई है। मेरीकॉम ने तो मणिपुर को ओलंपिक प्रदेश होने का गौरव दिलाया है, वहीं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर को खेल जगत में नई पहचान दी। अब यदि आकार प्रकार और जनसंख्या की दृष्टि से तुलना करें तो मणिपुर राजस्थान की तुलना में एक बहुत छोटा राज्य है, लेकिन खेल जगत में उसकी पहचान राजस्थान से बड़ी है। मुक्केबाजी में तो उसने इतिहास ही रच रखा है। हॉकी में भी मणिपुर का खास योगदान रहा है। खेल जगत में मेरीकॉम के उदय से पहले थोयबा सिंह ने हॉकी के मैदान में मणिपुर की पहचान बनाई थी। मणिपुर को छोड़िए, हमारे पडोसी राज्य हरियाणा और पंजाब को लीजिए। पंजाब ने हॉकी को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए। एक दौर वह भी रहा जब बिना सिख खिलाड़ियों के भारतीय हॉकी टीम की कल्पना करना भी असंभव सा लगात था। वहीं हरियाणा ने पिछल डेढ़-दो दशक में कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे दमखम वालों खेलों में अपनी पहचान बनाई है और उसमें निरंतरता बनाए हुए है, वैसा राजस्थान नहीं कर पाया है। कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ के बाद राजस्थान का कोई और खिलाड़ी ओलंपिक पदक नहीं लेकर आ सका। हां, पैरा ओलंपिक में जरूर राजस्थानी खिलाड़ियों ने अपनी चमक दिखाई है। हालांकि, कर्नल राठौड के बाद राजस्थान के युवाओं में शूटिंग के प्रति रूचि बढ़ी है और वे इस ओर आकर्षित हुए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान की महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वे देश और राजस्थान का गौरव बढ़ाएंगे। महेश्वरी और अनंतजीत स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में एकमात्र भारतीय जोड़ी के रूप में ओलंपिक में भाग लेंगे।

यानी राजस्थानी खिलाड़ियों ने ओलंपिक व एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन राज्य में एक खेल संस्कृति का विकास नहीं हो पाया जो इस खेल जगत की एक ताकत बना देता। अपने पड़ोसी पंजाब, हरियाणा या सुदूरवर्ती मणिपुर जैसी पहचान बना पाता। श्रीराम सिंह, मगन सिंह, हमीदा बानो, कृष्णा पूनिया सहित कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी, परंतु उसमें निरंतरता का अभाव बना रहा। इसकी एक वजह यह भी रही कि प्रदेश में जमीनी स्तर पर ऐसी खेल संस्कृति विकसित नहीं हो सकी, जहां खेलों के प्रति स्वाभाविक रूचि विकसित हो। हां, करीब चार दशक पहले कोटा रेलवे व डीसीएम हॉकी खिलाडियों के लिए संरक्षक बनकर उभरे थे, लेकिन समय के साथ वहां की चमक भी धुंधली पड़ गई, लेकिन अब सरकार की यह नई पहल उम्मीद जगाती है कि प्रदेश में नई खेल संस्कृति विकसित हो सकती है। हालांकि इस घोषणा को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। स्कूल खोलने के साथ कैच द यंग जैसा अभियान भी चलना पड़ेगा, जहां नैसर्गिक खेल प्रतिभाओं को स्कूली स्तर पर खोज और पहचान कर उनके प्रशिक्षण का इंतजाम किया जाए और उसमें निरंतरता बनाई रखी जाए। हालांकि पहले भी नई प्रतिभाओं को खोजने के प्रयास हुए हैं, लेकिन स्थिति में अपक्षित सुधार नहीं हो पाया है। राजस्थान में खेलों से जुड़ी हस्तियों का मानना है कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए मिशनरी भावना से काम करने की जरूरत है। जब तक खेलों से जुड़ा बुनियादी ढांचा तैयार नहीं होगा, तब तक बेहतर खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। अतः बुनियाद ढांचे के विकास के लिए कदम उठाने होंगे। उम्मीद है कि राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन राज्य में खेलों की कायाकल्प कर सकेगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

विश्व जनसंख्या दिवस आज

प्रभावी जनसंख्या नीति की दरकार

अरविंद जयतिलक
स्वतंत्र टिप्पणीकार

"भारत में पिछले एक दशक में भूखमरी की समस्या से जुझने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इफको की रिपोर्ट में भी कहा जा चुका है कि कुपोषण की वजह से देश के लोगों का शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बनता जा रहा है। गौर करें तो कुपोषण वास्तव में घरेलू खाद्य असुरक्षा का सीधा परिणाम है। लोगों तक खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करके ही कुपोषण को मिटाया जा सकता है।"

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज की तारीख में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। चीन की आबादी 142.57 करोड़ है जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ के पार पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के आंकड़ों के मुताबिक चीन के मुकाबले अब भारत की जनसंख्या अधिक हैं। यह पहली बार है जब भारत जनसंख्या सूची में शीर्ष पायदान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्य केरल और पंजाब में बुजुर्गों की संख्या अधिक है वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी सर्वाधिक है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी आने वाले तीन दशकों तक बढ़ती रहेगी और उसके बाद घटनी शुरु होगी। यानि 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के पार पहुंच सकता है। उधर, चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ रह जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक जब दुनिया भर में जनसंख्या बढ़ने की गति धीमी पड़ रही है वहीं भारत में साल भर में आबादी 1.56 फीसद बढ़ी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि इसलिए है कि नवजात, शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट आयी है। एक आंकड़े के मुताबिक 2012 में एक वर्ष के कम उम्र के बच्चों की मौत की दर 42 प्रति हजार थी जो 2020 में घटकर 28 प्रति हजार रह गयी है। इसी तरह पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर 52 से घटकर 32 रह गयी है। यह रेखांकित करता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के मुताबिक अर्थव्यवस्था को आकार देना बेहद जरुरी है। इस जनसंख्या वृद्धि का सकारात्मक पहलू यह है कि भारत दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश बन चुका है लेकिन एक सच यह भी है कि बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष संसाधनों की कमी और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां बढ़ेगी। इसलिए कि अनुकूलतम जनसंख्या के बिना विकास के अपेक्षित लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि विगत पांच दशकों में जनसंख्या में निरंतर तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन हो गयी है। विशेषज्ञों की मानें तो जनसंख्या की यह तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है और कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निर्धनता में वृद्धि,

मकानों की समस्याएं, कीमतों में वृद्धि, कृषि विकास में बाधा, बचत तथा पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय, अपराधों में वृद्धि तथा शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी ढ़ेर सारी समस्याएं उत्पन हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। देश में पूंजीगत साधनों की कमी के कारण रोजगार मिलने में कठिनाई उत्पन हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में बेरोजगारी की दर चिंताजनक है।

यह हालात तब है जब देश में बेरोजगारी से निपटने के लिए ढ़ेर सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) सर्वाधिक रुप से महत्वपूर्ण हैं। सीआईआई की इंडिया स्किल रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल तकरीबन सवा करोड़ शिक्षित युवा तैयार होते हैं। ये नौजवान रोजगार के लिए सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन सिर्फ 37 फीसद ही कामयाब हो पाते हैं। गौर करें तो रोजगार न मिलने के दो कारण हैं। एक, यह कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लगातार सिकुड़ रही हैं वहीं दूसरी ओर प्राइवेट क्षेत्र में उन्हीं लोगों को रोजगार मिल रहा है जिन्हें कारोबारी प्रशिक्षण हासिल है।

सबसे अधिक बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन अगर गांव के पढ़े-लिखे नौजवानों को बागवानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, कृषि यंत्रों की मरम्मत के संबंध में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए तो बेरोजगारी से निपटने में मदद मिलेगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम पड़ रही है जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और उनकी कार्यकुशलता घट रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कुपोषण की समस्या भी लगातार सघन हो रही है। यूनाइटेड नेशन के फुड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से उद्घाटित हो चुका है कि भारत में पिछले एक दशक में भूखमरी की समस्या से जुझने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इफको की रिपोर्ट में भी कहा जा चुका है कि कुपोषण की वजह से देश के लोगों का शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बनता जा रहा है। गौर करें तो कुपोषण वास्तव में घरेलू खाद्य असुरक्षा का सीधा परिणाम है। लोगों तक खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करके ही कुपोषण को मिटाया जा सकता है। भारत में कुपोषण का सर्वाधिक संकट महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। हर वर्ष लाखों गर्भवती महिलाएं उचित पोषण के अभाव में दम तोड़ रही हैं।

दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी स्थिति में है। गत वर्ष पहले एसीएफ की रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ था कि भारत में कुपोषण जितनी बडी समस्या है वैसे पूरे दक्षिण एशिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। यह दर्शाता है कि आर्थिक नियोजन के साढ़े छः दशक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह निर्धनता के दुष्कचक्र में फंसी हुई है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में मकानों की समस्या भी लगातार गहरा रही है। आजादी के सात दशक बाद भी आज देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुविधाहीन झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन गुजारने को विवश हैं। गौर करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में बेघरों की संख्या तीन करोड़ के आसपास है। कुछ ऐसा ही हाल शहरों का भी है। गत वर्ष पहले अर्थव्यवस्था और वातावरण पर आधारित केंद्रित वैश्विक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2031 तक भारत की शहरी आबादी 60 करोड़ हो जाएगी। मतलब साफ है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगा तो आवासों की समस्या और गहराएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों में वृद्धि से भूमि का उप-विभाजन और विखंडन बढ़ता जा रहा है। इससे खेतों का आकार छोटा तथा अनार्थिक होता जा रहा है। इसका कुपरिणाम यह है कि देश में भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से बचत तथा पूंजी निर्माण में भी कमी आ रही है। भारत की जनसंख्या में 36 फीसद बच्चे हैं। नतीजा कमाने वाले लोगों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के पालन-पोषण पर खर्च करना पड़ रहा है। इससे बचत घट रही है और पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

पूंजी की कमी के कारण विकास योजनाओं को पूर्ण करने में कठिनाई उत्पन हो रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण सरकार को बिजली, परिवहन, चिकित्सा, जल-आपूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है जिससे अन्य क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। दो राय नहीं कि राष्ट्र के विकास में जनसंख्या की महती भूमिका भी है। विश्व के सभी संसाधनों में सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वप्रमुख संसाधन मानव संसाधन ही है। लेकिन अतिशय जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में जरुरी हो जाता है कि भारत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए नई जनसंख्या नीति को आकार दे। इस पर गहनता से विचार करे कि आखिर भारत के लिए अनुकूलतम जनसंख्या क्या हो? इसलिए कि अभी तक जितनी भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी है उसका सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना तथा स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर देना इत्यादि का लक्ष्य रखा गया था। कमोवेश इसी तरह का उद्देश्य और लक्ष्य वर्ष 2000 की नई राष्ट्रीय नीति में भी रखा गया। लेकिन जिस गति से आबादी में इजाफा हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यंग्य

बेनिफिट्स ऑफ रेन

सुनील कुमार महला
व्यंग्यकार

बारिश के मौसम पर यूं तो बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन क़तील शिफ़ाई कुछ यूं लिखते हैं -' दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।' आजकल संपूर्ण भारत में जगह जगह खूब बारिश हो रही है। आदमी पहले गर्मी से परेशान था, आजकल बारिश से। पहले लोग बारिश आने के लिए यज्ञ और हवन करते हैं और बाद में बारिश रोकने के लिए। बड़ा झंझट है बारिश का। बारिश आती है तो लोग घरों के अंदर घुसते हैं और बारिश का पानी नालियों में घुसना पसंद नहीं करता, पानी नालियों से बाहर बिखरता है। दरअसल, बारिश का पानी पालीथीन बैग्स व कचरे के साथ खेलता है।

अजी! कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बारिश प्रेमी-प्रेमिका के रोमांस का ही सीजन नहीं है। नालियों का पानी भी सड़क व गलियों से अच्छा खासा रोमांस करता है। बारिश से नालियां, सड़कें, खडडे पानी से भर जाते हैं और हमारी गाड़ियां गंदी हो जाती है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अजी! बारिश के अपने फायदे हैं।कार वाशिंग करने वालों, लांड्री वालों व ठेकेदारों को काम मिलता है। बेरोजगारी का नामोनिशान तक नहीं बचता। वैसे बारिश का सबसे ज्यादा फायदा सड़कों व पुलों का ठेका लेने वालों को होता है। सड़कें और पुल बारिश में बह जाते हैं और ठेकेदारों को अनाप-शनाप काम पर काम मिलता है। फटाक से देश से बेरोजगारी दूर होती है। पकौड़े तलने वालों को भी बारिश में अच्छा खासा काम मिल जाता है।

आइसक्रीम बेचने वाले पकौड़ा व्यवसाय की ओर पलायन करने लगते हैं। भरी गर्मी में बारिश आने से चाय और कॉफी वालों का मंद पड़ा धंधा चमकने लगता है। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को बारिश में गाने फिल्माने का काम मिल जाता है। उन्हें आर्टिफिशियल बारिश का झंझट नहीं पालना पड़ता। इतना ही नहीं अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को मेकअप को धोने का भी झंझट नहीं करना पड़ता। बारिश में मेकअप अपने आप धुल जाता है। एक फायदा बारिश का यह भी है कि बारिश में पानी मुफ्त में मिलता है, पानी के टैंकर गिराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। साबुन और वाशिंग पाउडर इंडस्ट्री का खूब माल बिकने लगता है। बारिश में पानी के लिए मोटर भी नहीं चलानी पड़ती। आदमी को भगवान को ही अरदास करनी पड़ती है कि 'भगवान जी अब तो मोटर बंद कर दीजिए, पानी फुल हो गया है।' बारिश का एक मजा यह भी है कि आप नावों को ही नहीं कारों, मोटरसाइकिलों व अन्य साधनों को भी तैरता हुआ देख सकते हैं। वैसे बारिश का एक फायदा यह भी है कि हम सड़कों को धान रोपाई व स्वीमिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं।

और तो और थोड़ी बहुत बारिश में कैब वाले स्वयं को भगवान मान बैठते हैं। बारिश का एक आनंद यह भी है कि आपको बार-बार बाथरूम के अंदर जा कर नहाना नहीं पड़ता। बारिश का फायदा क्रिकेट मैच में भी होता है। गीली आउटफील्ड के कारण बालरों को कम ओवर करने पड़ते हैं, इससे वे थकते नहीं हैं। बहुत बार न जीतने वाली टीम भी बारिश के कारण जीत जाती है। अधिक बारिश से स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। बारिश के कारण 'लू' लापता हो जाती है तो इधर छाते व रेनकोट बेचने वालों की मौसमी बेरोजगारी दूर हो जाती है। हमारे शहर में भी इन दिनों गर्मी राहत कैंप लगा हुआ है, व्यंग्य लिखने से आजकल काम नहीं चल रहा है, इसलिए बारिश के इस मौसम में हम भी पकौड़े तलने जा रहे हैं। जय राम जी की। गुस्ताख़ी माफ़।

जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा ही नहीं जरूरत भी...

अर्चना त्यागी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

सारी खुराफात, सारी हुड़दंग बाजी लड़कों के लिए ही है। मुसीबत हो जाती है जब पुत्र मोह और सरकारी नौकरी दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है।

यह कहने की बात नहीं है कि बढ़ती आबादी हमारी आज़ादी को सीमित करती आ रही है।

इंसानों के बढ़ने से संसाधन कम हो रहे हैं। रोजगार के अवसर घट रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। अराजकता का माहौल स्थायी हो गया है। ऐसे में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यदि कोई कदम उठाया जाता है तो उसका स्वागत करने के बजाय राजनीति करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ? सभी विपक्षी दल एक जुट होकर कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्हे बढ़ती आबादी से उत्पन्न समस्याएं नज़र नहीं आती हैं। अपने कार्यकाल में बढ़ती आबादी को लेकर वो कोई कानून नहीं बना पाए, क्या यह भी

विरोध का एक कारण है ? या फिर देश की समस्याओं को भूलकर सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करना ही उन्होंने अपना धर्म मान लिया है। ऐसा लगता है कि कुर्सी भगवान है और उसे पाने की जोड़ तोड़ ही एकमात्र काम है जो राजनेताओं को करना चाहिए। कानून से उन्हें समस्या है जिन्हे पुत्र रत्न की प्राप्ति तक संतान उत्पन्न करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। जो आज़ भी लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं और लड़कों को बोर्डिंग में पढ़ने भेजते हैं। जिन्हे आज़ भी लगता है कि पढ़ लिखकर लड़कियां घर नहीं चला सकती हैं। लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं। सारी खुराफात, सारी हुड़दंग बाजी लड़कों के लिए ही है। मुसीबत हो जाती है जब पुत्र मोह और सरकारी नौकरी दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है।

परेशानी उन्हे भी है जो औलाद पैदा करना खुदा का हुक्म मानने के समान ही मानते हैं। यह अलग बात है कि पैदा करने के बाद अच्छी परवरिश दें पाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। जाने कब भारतवासी धर्म से ऊपर उठकर सोचेंगे ? कब उन्हें यह समझ आएगा कि पुत्र पैदा करने मात्र से ही मोक्ष नहीं मिलता है। खुदा बंदे पैदा करने की सहूलियत के साथ साथ उनकी हिफाजत करने को भी कहता है। संतान उत्पत्ति से वंश को आगे बढ़ाने के साथ ही देश के प्रति भी हमारा नैतिक दायित्व है। जो बच्चा दुनिया में आए उसे अच्छी परवरिश मिले ताकि देश को सभ्य, शिक्षित और संस्कारी नागरिक मिल सकें जो उसकी प्रगति में सहायक हों। धर्म को मानते हुए देशभक्त होना भी आवश्यक है। यह प्रत्येक भारतवासी की ज़िम्मेदारी है कि देशहित में अपने व्यक्तिगत निर्णय ले। सही और गलत मे अंतर पहचान सके। केवल इस आधार पर किसी कानून का विरोध नहीं किया जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी को नीचा दिखाना है। पार्टियां आती जाती रहती हैं। सही बात कहने वाले और उस पर टिके रहने वाले कभी कभी आते हैं। गलती से यदि कोई निर्णय देश के हित में लिया जाए तो निजी स्वार्थ के चलते उसका विरोध नहीं बल्कि समर्थन होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जनता जागरूक हो। अपने हित में आवाज़ उठाए और पक्ष विपक्ष की भूल भुलैया से निकलकर अपने अधिकार और कर्तव्यों को पहचाने। तभी इन दोहरे चरित्र वाले राजनेताओं की आंख खुलेगी।

X

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
@AmitShah
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ हैं।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
@myogiadityanath
युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं के हितों के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है... प्रदेश में 62 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम किया गया है। अभी और 4,700 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है।

बिहार में बदलेंगे सियासी समीकरण: प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर करेंगे नई पार्टी शुरू

सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, दलितों व मुस्लिमों पर खेलेंगे बड़ा दांव

एजेंसी | पटना

चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे।

किशोर ने यह भी कहा है कि उससे पहले वह 21 नेताओं की एक कमेटी गठित करेंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। प्रशांत की इस घोषणा से बिहार के सियासी परिदृश्य में बदलाव आने की संभावना है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

प्रशांत किशोर ने दो साल पहले 2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती के मौके पर ही पश्चिम चंपारण से जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। पिछले दो साल में किशोर राज्यभर में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। वह अपनी जनसभाओं में लोगों को जाति के कुचक्र से ऊपर उठकर विधायक-सांसद चुनने की अपील

करते रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह आगामी विधान सभा चुनावों में महागठबंधन और राजग के खिलाफ अपने बुते पर चुनाव मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि वह 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे। किशोर अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि बिहार के मुसलमान डर कर वोट करते रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर दलितों पर भी बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। राज्य की आबादी में दलितों और मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी 37 फीसदी है। इसलिए वह बड़ी संख्या में दलितों को भी चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

क्या है रणनीति

- 75 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करेंगे
- दलितों की भी होगी बड़ी भागीदारी
- दलितों और मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी 37 फीसदी
- 21 नेताओं की एक कमेटी देखेगी पार्टी के मामले

नीतीश व लालू के वोट बैंक में सेंधमारी संभव

प्रशांत किशोर की राजनीतिक शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से हुई है। 2015 के विधान सभा चुनावों में जीत के बाद नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी में नंबर दो की हैसियत दी थी, लेकिन जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब प्रशांत किशोर नीतीश के दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर इसी रणनीति से लालू यादव की पार्टी राजद के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है लेकिन उन्होंने ने साफ किया है कि वह सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर भाजपा को भी सबक सिखाएंगे।

CBI केस में बंगाल की याचिका पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों को सीबीआई जांच के लिए भेजी जाती है। इसके बाद उन मामलों की एकतरफा जांच होती है। वहीं, इन मामलों पर केद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने माना कि इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। बंगाल सरकार का कहना है कि सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्र सरकार सीबीआई को जांच के लिए राज्य में भेज रही है। राज्य में सीबीआई ने 15 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। शीर्ष अदालत ने 8 मई को राज्य द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाथरस मामले में भाजपा सरकार विफल: अखिलेश

इटावा। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस हादसे में भाजपा सरकार फेल हुई है। यहां पर प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो की है और यह माना भी है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं हुई थी। अखिलेश यादव यहां स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए गए थे वह आज भी बरकरार हैं। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। पूरे प्रदेश में जलभराव के हालात हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेकार हो गई हैं, लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं।

उपचुनाव: छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रही सियासी परीक्षा

सात राज्यों में शक्ति परीक्षण, तेरह विधानसभा सीटों पर 63% मतदान

एजेंसी | नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के बाद देश के सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बुधवार को 63.23 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ। छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा। इन सीटों पर उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या उनके इस्तीफे के कारण कराया गया। मतगणना 13 जुलाई को होगी।

इसके साथ ही इन 13 सीटों पर चुनाव मैदान उतरे सभी 121 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज नेता और कुछ नए चेहरे चुनाव मैदान में थे।

13 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 78.38 फीसदी मतदान मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर हुआ है। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम 47.68 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है।

हालांकि, अभी अंतिम आंकड़े आना बाकी है। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ है, वहां पिछली भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक तीन-तीन सीटें जीती थीं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस ने दो सीटें जीती थीं। वहीं टीएमसी, बसपा, जदयू, आप और डीएमके के एक-एक उम्मीदवार विजयी हुए थे।

इन सीटों पर हुआ मतदान

मतदान पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार के रूपौली, तमिलनाडु की विक्रवंडी और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए हुआ। उपचुनाव पर सभी प्रमुख दलों की नजर है।

हिमाचल प्रदेश की तीन सीटों पर 71 प्रतिशत मतदान

हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 71 प्रतिशत मतदान हुआ. इसमें नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 78.1 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद हमीरपुर में 67.1 और देहरा में 65.2 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। ये तीनों सीटें निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और के. एल. ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफा के बाद खाली हुई थीं। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डाला था। इसके बाद वे भाजपा में शामिल भी हो गए थे।

पश्चिम बंगाल: उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा-TMC समर्थक भिड़े

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा-टीमएसी समर्थक बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक-दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मामला शांत कराया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे चौराहे पर खड़े होकर वोटिंग करने जा रहे लोगों को रोक रहे हैं। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर झड़प के बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बिहार में पूर्णिया की रूपौली सीट पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पुलिस की माने तो बूथ के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने हटने को कहा तो बहस शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। एक एसएचओ और सिपाही घायल हो गए।

सीएम केजरीवाल को राहत नहीं

जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध खारिज

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है। ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बुधवार को मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें मंगलवार देर रात दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के दावे को चुनौती दी। सिंघवी ने कहा कि जवाबी प्रति मंगलवार दोपहर 1 बजे जांच कार्यालय (आईओ) को भेज दी गई। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत जल्दी है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वह अपने जवाबी हलफनामे पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जस्टिस कृष्णा ने टिप्पणी की कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हकदार है। कोर्ट ने मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

मणिपुर भाजपा विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक

मैतेई-कुकी में सुलह के प्रयास: सिंह

एजेंसी | इंफाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के दो दिन बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य का दौरा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम 24 घंटे प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं।

बता दें कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी से हिंसा से प्रभावित राज्य में जाकर लोगों को सांत्वना देने का अनुरोध किया था। ज्ञात रहे कि राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में पिछले साल मई से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है सिंह ने राज्य भाजपा की विस्तारित

कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, कि राज्य के दोनों समुदायों के बीच सुलह के प्रयास जारी हैं। हमें मुद्दों को सुलझाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम चौबीसों घंटे प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आना स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि, सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 'स्थिति' से उनका क्या मतलब है।

कुकी बहुल इलाकों में 12 घंटे का पूर्ण बंद

वहीं राज्य में एक प्रमुख कुकी संगठन की तरफ से समुदाय से जुड़े पांच लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में 12 घंटे के पूर्ण बंद के कारण मणिपुर के चार जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कि कुकी इंपी की तरफ से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल के आह्वान के कारण चुराचंदपुर, कांगपोकपी, फेरजावल और तेंगनौपाल जिलों में बाजार, शैक्षणिक संस्थान और बैंक बंद रहे। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति कम रही।

संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कल से

विस्तार व सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर मंथन

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 12 से 14 जुलाई तक झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनावों के बाद होने वाली इस बैठक में देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जा सकती है।

संघ के अनुसार इस बैठक के शताब्दी वर्ष में संगठन के विस्तार और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। शताब्दी वर्ष में संघ देश के प्रमुख लोगों से मिलकर राष्ट्रनिर्माण में उनकी भूमिका का बेहतर उपयोग करने के तरीकों

पर भी विचार करेगा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक में पूरे देश भर से संघ के संगठन की दृष्टि से बनाए गए 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में संघ के विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। प्रतिवर्ष संघ की तीन महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं। इस बैठक में हाल ही में सम्पन्न हुए प्रशिक्षण वर्ग एवं विभिन्न विषयों और उनके क्रियान्वयन सहित संघ के सभी कार्य विभाग के कार्यों पर चर्चा होगी। आंबेकर के अनुसार, बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत के देश भर में प्रवास के विषय पर भी चर्चा होगी। वर्तमान में देशभर में 73 हजार शाखाएं संचालित की जा रही हैं। आगामी शताब्दी वर्ष में देशभर के अंदर सभी मंडल स्तर तक कम से कम एक शाखा हो, इसकी योजना पर कार्य हो रहा है। इसके साथ ही नगरों में बस्ती तक संघ के सेवा कार्य, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पहुंचने की कोशिश की जाए, इसकी भी योजना बनाई जाएगी। सुनील आंबेकर ने बताया कि 2025-26 संघ का शताब्दी वर्ष है और इन वर्षों में सामाजिक परिवर्तन के पंच उपक्रम को शाखा स्तर और समाज तक पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव

क्रॉस वोटिंग की आशंका से डरी पार्टियां, MLA को एकजुट रखने में जुटी

एजेंसी | मुंबई

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। राज्य में विधान परिषद चुनाव 12 जुलाई को होने हैं। ऐसे में अब सभी दल ऐहतियात के तौर पर विधायकों की बैठकें और रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव खासे रोचक हो गए हैं तथा क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। राजग और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों के घटक दल अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। दोनों खेमों की ओर से कोशिश है कि अपने विधायकों को एकजुट

रखा जाए और दूसरे के तोड़ लिए जाएं। इस कोशिश में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें होटलों की बुकिंग शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार इस बार कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार से ज्यादा बेचैनी इस बार राजग खेमे में है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि राजग के पास ज्यादा विधायक है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास तो अब एक-एक दर्जन विधायक ही बचे होंगे। वहीं कांग्रेस भी बेफिक्र दिख रही है। उसने गुरुवार को विधायकों के लिए लंच का आयोजन किया है, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे विधान परिषद चुनाव में वोटिंग करनी है।

नार्वेकर के मैदान में होने से आशंकित है शिंदे नीत शिवसेना

सूत्रों के अनुसार भाजपा और शिंदे नीत शिवसेना के विधायकों को अलग-अलग ठहराया जा सकता है। ज्ञात रहे कि उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने मिलिंद नार्वेकर को चुनाव मैदान में उतारा है। नार्वेकर उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर ले। हालांकि क्रॉस वोटिंग डर सभी दलों में है। अब तक की जानकारी के अनुसार विधायकों को मुंबई से थोड़ा बाहर के इलाकों में रखा जा सकता है और ये वोटिंग से ठीक पहले लाए जाएंगे।

होटल बुक कराने में जुटे महायुति के दल

वहीं भाजपा, एकनाथ शिंदे सेना और अजित पवार गुट होटलों की बुकिंग में जुटे हैं ताकि विधायकों को एकसाथ रखा जा सके। ऐसा इसलिए कि क्रॉस वोटिंग का डर है। खासतौर पर एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार नीत राकांपा के विधायकों के टूटने का डर है। लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसी रिपोर्ट्स लगातार रही हैं कि कई विधायक अपनी वफादारी फिर से बदल सकते हैं। इसलिए इन्हें होटलों में रखने की कोशिश है। हालांकि अनंत अंबानी के विवाह के चलते मुंबई में फाइव स्टार होटल फुल हैं और कमरे मिलना मुश्किल हो रहा है। इस शादी के लिए लिए देश-विदेश से वीआईपी मेहमान आए हुए हैं। इसलिए साउथ मुंबई इलाके के ज्यादातर फाइव स्टार होटल बुक हो चुके हैं।

राजग का संयुक्त रणनीति पर विचार, फडणवीस को सौंपी कमान

दो दिन पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की बैठक हुई थी। इस बैठक में तीनों दलों ने संयुक्त रणनीति पर विचार किया। इसके अलावा वोटिंग पैटर्न तय करने का फैसला किया है। बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया कि तीनों दलों को प्रथम और द्वितीय वरीयता के वोट कैसे दिए जाएंगे। दरअसल 2022 में भाजपा ने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। तब कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में थी। उस अनुभव को देखते हुए इस बार भी राजग की कमान फडणवीस को ही दी गई है।

यह है दावेदारी

ज्ञात दें कि कुल 11 सीटों के लिए जो 12 कैंडिडेट उतरे हैं, उनमें से 5 भाजपा के हैं। इसके अलावा दो-दो उम्मीदवार एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के हैं। विपक्ष के महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों ने एक-एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है।

जरूरी खबर

दूध के टैंकर से टकराई बस, 18 लोग मरे

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ -आगरा एक्सप्रेस वे पर हुई इस दुर्घटना में डबल डेकर बस पीछे से कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा घायल हो गए।। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार स्लीपर बस बिहार के शिवहर से दिल्ली की ओर जा रही थी। यह घटना उन्नाव के थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के तहत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या-247 पर हुई। इसमें डबल डेकर बस ने पीछे से दूध से भरे टैंकर में टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर सभी घायलों को बाहर निकाल कर सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती करवाया गया।

T20: भारत ने तीसरे मैच में भी जिम्बाब्वे को हराया

हरारे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने 23 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। सिकंदर रजा की टीम एक बार फिर गेंद और बल्ले से फ्लॉप साबित हुई। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में चार विकेट पर 182 रन बनाए। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ा।

इसरो जासूसी कांड में झूठा फंसाया गया था

तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में इसरो जासूसी कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 1994 का इसरो जासूसी कांड केरल के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के दिमाग की उपज था। उसने मालदीव की एक महिला को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए यह केस बनाया था। महिला ने उस पुलिस अधिकारी के प्रयासों को ठुकरा दिया था। सीबीआई ने कहा कि इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को झूठा फंसाया गया था।

ऑस्ट्रिया के दौरे पर पीएम मोदी... स्वागत... सत्कार और मुलाकात

वियना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। वियना पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।

पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात

निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं, संवाद व कूटनीति पर जोर

एजेंसी | वियना (ऑस्ट्रिया)

रूस की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक और यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। उन्होंने वहां ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक संघर्षों विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को सुलझाने में 'वार्ता और कूटनीति' के महत्व पर जोर दिया। वहीं

भारत-ऑस्ट्रिया संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। यह टिप्पणी वियना में संघीय चांसलरी में चांसलर नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आई। पीएम मोदी ने कहा, हम युद्ध के मैदान में समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। चाहे वह कहीं भी हो, निर्दोष लोगों की हत्या अस्वीकार्य है। भारत और ऑस्ट्रिया संवाद और कूटनीति पर जोर देते हैं और इसके लिए हम किसी भी तरह की सहायता देने के लिए तैयार हैं।

आतंकवाद की कठोर निंदा

पीएम मोदी ने कहा भारत और ऑस्ट्रिया, आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं जाएगा। आतंकवाद किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं हो सकता। हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव के लिए सहमत हैं, ताकि उन्हें मजबूत बनाया जाए।

पीएम मोदी का आपसी सहयोग पर जोर

पीएम मोदी ने कहा, हमने आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। ढांचागत विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन और क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और विचारों को जोड़ने के लिए स्टार्ट अप को गति दी जाएगी।

ऑस्ट्रिया ने किया पंडित नेहरू के योगदान को याद

पीएम मोदी के साथ चर्चा के दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक बेहद पुरानी बात को याद करते हुए कहा कि भारत ने 1955 में ऑस्ट्रिया के स्वयंप्रभु राष्ट्र बनने में भारत ने मदद की थी। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पर चार सहयोगी शक्तियों (अमेरिका, रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) , ब्रिटेन, और फ्रांस) का कब्जा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतराष्ट्रीय मंचों पर ऑस्ट्रिया के समर्थन में जोर दिया। भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि ऑस्ट्रिया को एक स्वतंत्र और तटस्थ देश के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि वह दोनों विश्व युद्धों के दौरान हुए संघर्षों से बाहर रह सके।

भव्य स्वागत, मजबूत दोस्ती का वादा

इससे पहले वियना पहुंचने पर पीएम मोदी का चांसलर कार्ल नेहमर ने भव्य स्वागत किया । पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर उतरते ही चांसलर नेहमर ने उन्हें गले लगाया। फिर उनके साथ सेल्फी ली और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। उनके लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। इस दौरान दोनों की गले मिलते हुए एक तस्वीर भी सामने आई। जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें चांसलर नेहमर ने ट्वीट कीं। नेहमर के ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत-ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है, आने वाले समय में यह और मजबूत होगी। दोनों देश वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

NEET मामले में केंद्र का SC में हलफनामा

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के नहीं है सबूत

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। जिसमें सरकार ने आईआईटी मद्रास के डेटा का हवाला देते हुए कहा है कि उसे परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं और वह दोबारा परीक्षा के समर्थन में नहीं है। केंद्र ने कहा कि वह देश भर में नीट की परीक्षा दे चुके छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है। काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार 11 जुलाई को सुनवाई करने वाला है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि वह दोबारा परीक्षा के समर्थन में नहीं है और वह यह सुनिश्चित कर रही है कि इस मामले में दोषी किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ न मिले। सरकार ने हलफनामे में कहा कि नीट -यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित डेटा पर एक विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया था और विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि डेटा विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि छात्रों के किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी स्थानीय समूह को इसका लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार ने कहा कि उसने पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का संचालन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

CRPF और सेना ने की इलाके में घेराबंदी

अब ऊधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़

एजेंसी | ऊधमपुर

कठुआ में आतंकी हमले के बाद अब ऊधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। संग और मंग इलाके में पुलिस पोस्ट के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। बताया जा रहा है बुधवार रात आठ बजे के करीब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई है। एसओजी, सीआरपीएफ और सेना आतंकियों की घेराबंदी कर रही है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों के 10-15 राउंड फायर करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। जंगलों की आड़ और अंधेरे की वजह से मुठभेड़ को रोकना पड़ा। ऊधमपुर के एसएसपी जोगिंदर सिंह ने कहा कि उधमपुर जिले के बसंतगढ़ तहसील के संग पुलिस पिकेट में गोलीबारी की खबर मिली है। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इससे पहले 28 अप्रैल 2024 को आतंकियों ने बसंतगढ़ के चोचरू गला में आतंकियों ने एसपीओ और ग्राम रक्षक दल पर घात लगा कर हमला किया था। इसमें ग्राम रक्षक दल का एक सदस्य शहीद हो गया था।

उच्चतम न्यायालय का अहम फैसला

मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए व्यवस्था दी है कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सीआरपीसी की

धारा 125 (गुजारा भत्ता प्राप्त करने के प्रविधान) सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओ पर भी लागू होती है। कोर्ट ने फैसले में परित्यक्ता, बेसहारा और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ महिलाओं की आर्थिक और आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया है। फैसले में एक साथ तीन तलाक रोकने के लिए लाए गए कानून मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत दिए गए गैरकानूनी तलाक की पीड़िता के गुजारा भत्ते के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं। फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

आईएचएफ़ ट्रॉफी हैंडबॉल में भारत की विजयी शुरुआत

रवि के डेढ़ दर्जन गोल की बदौलत बांग्लादेश को 45-35 से हराया

बेधड़क | जयपुर

आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल चैम्पियनशिप में बुधवार को यूथ (अंडर-18) वर्ग में मेजबान भारत ने अपना विजयी अभियान शुरू करते हुए कप्तान रवि के शानदार 15 गोलों की बदौलत बांग्लादेश को 45-35 गोल से पराजित किया। माध्यतर तक भारत ने 27-16 गोल की बढ़त बनाए हुए था।

मैच के मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर चुने गए रवि पूरे मैच में छाये रहे। उसने 15 गोल के अलावा साथी खिलाड़ियों के साथ शानदार तालमेल भी बनाया। उसके अलावा प्रवीण गिल ने 9, रोहित-रोहित ने 8-8, मनीष यादव व नवदीप ने 2-2 और प्रवेश ने 1 गोल किया।

बांग्लादेश के लिए मोहम्मद अतीक हुसैन आकाश ने सर्वाधिक 7 गोल किए। तोफिक कूर रहमान, मोहम्मद इबादत हुसैन रासेल ने 6-6, मोहम्मद सोहाग अली ने 5, मोहम्मद फहीम फेजल माहिर ने 4, मोहम्मद रातुलिदीन, मोहम्मद अनिक इस्लाम ने 3-3 और रिजवान बिन फारूक अन्नान ने 1 गोल का योगदान दिया। दक्षिण एशियाई हैंडबॉल महासंघ के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पांडे ने भारत के रवि को पुरस्कार दिया।

इससे पहले जूनियर (अंडर-20) के रोमांचक मैच में मालदीव ने नेपाल को हराया। पहले हॉफ (13-14) में एक गोल से पिछड़ने के बाद दूसरे हॉफ में शानदार वापसी करते हुए मालदीव ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 28 के मुकाबले 30 गोल से हराया। मालदीव के लिए मोहम्मद यशमू अहमद ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 10 गोल किए। इसके अलावा मोहम्मद अफानाथी ने 7, अहमद राउल असद ने 6, मोहम्मद अमसाल ने 2, मुसा हिबाह इस्माईल रिजा और अहमद उमेस ने 1-1 गोल का योगदान दिया।

नेपाल के लिए प्रलेश गौरांग ने 9, सुदीप घाले ने 8, दाबीन जुगलीपुन ने 5, जीवनपुन ने 3 और निशान परीयार ने 1 गोल का योगदान दिया। इस मैच के मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर मालदीव के हुसैन यानल अकरम रहे, जिन्हे साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष तेज गुरंग ने पुरस्कार दिया।

यूथ वर्ग में मालदीव ने नेपाल को हराया

बुधवार के सत्र के उदघाटन मैच में मालदीव ने यूथ वर्ग में नेपाल को कड़े मुकाबले में 36-31 गोल से हराया। मध्यातंर तक विजेता टीम 17-15 गोल से बढ़त ली हुई थी। इस मैच में मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर मालदीव के शाहिन लहूफान अहमद को चुना गया। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के एसोसिएट उपाध्यक्ष ललित कुमार कलाल ने शाहिन को पुरस्कृत किया।

आज खेले जाने वाले मैच

दोपहर 2 बजे
नेपाल बनाम बांग्लादेश (यूथ)

शाम 4 बजे
नेपाल बनाम बांग्लादेश (जूनियर)

शाम 6 बजे
भारत बनाम मालदीव (यूथ)

शाम 8 बजे
भारत बनाम मालदीव (जूनियर)

विक्की कौशल और एमी विर्क ने जयपुर में किया अपनी फिल्म बैड न्यूज का प्रमोशन

मेरी पसंद के पराठे अब कैटरीना की चॉइस... उनका पैन केक अब मेरा

बेधड़क.जयपुर। धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव के सहयोग से अमेजन प्राइम द्वारा प्रस्तुत, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'बैड न्यूज' की रिलीज डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, फैंस और दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर इसके प्रमोशन का सिलसिला भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म को प्रमोट करने के लिए इसके मुख्य कलाकार विक्की कौशल और एम्मी विर्क जयपुर पहुंचे। आनंद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एम्मी विर्क एकदम नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 19 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के प्रमोशन को लेकर जयपुर में दोनों कलाकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां उन्होंने फिल्म, अपने किरदारों और इसे लेकर अपने अनुभव पत्रकारों से शेयर किए।

जैसे सिम्पल बने रहना मुश्किल, वैसे मेरे लिए कॉमेडी

फिल्म 'बैड न्यूज' के प्रमोट करने बुधवार को जयपुर आए एक्टर विक्की कौशल और एमी विर्क ने राजमंदिर में फैंस से बात की। इस दौरान जब विक्की से कैटरीना से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने मजेदार अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी शादी के बाद दोनों में बदलाव आया है। मैं पराठे खाने वाला आदमी उनकी पसंद का पैन केक खा रहा हूं। वे पैन केक की जगह पराठे खाना पसंद कर रही हैं। विक्की ने कहा कि शादी के दो साल में मुझे अंग्रेजी भी उनकी वजह से सीखने को मिली है। यहां तक कि मेरी इस फिल्म में तौबा-तौबा गाने पर जो डांस किया है, वह भी उनकी वजह से ही शानदार हो पाया है। बता दें कि धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर बनी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'बैड न्यूज' 19 जुलाई को रिलीज होगी। विक्की ने कहा कि कॉमेडी मुझे बेहद मुश्किल लगती है। मैंने रोम-कॉम (रामेंटिक कॉमेडी) फिल्में की हैं, लेकिन बैड न्यूज फुल कॉमेडी मूवी है। ऐसे में यह काफी चैलेंजिंग रही। कहते हैं न सिम्पल बने रहना मुश्किल है, वैसे ही मेरे लिए भी कॉमेडी मुश्किल रही। इसे करने में काफी मजा आया।

दो पंजाबियों में कैमिस्ट्री बन ही जाती है

विक्की ने बताया कि जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी, तब हम पूछ रहे थे कि इस तरह की घटनाएं हुई है क्या। तब हमें पता लगा था कि इस तरह के बाप 15 के करीब हैं। अब यहां मेम ने हमें 19 ऐसे केस के बारे में बताया है। इस को हमने सिचुवेशनल कॉमेडी की तरह बनाया है। विक्की ने एमी के साथ कैमिस्ट्री पर कहा कि जब दो पंजाबी मिलते हैं तो कैमिस्ट्री अपने आप बन जाती है। बाकियों में आइस ब्रेकिंग करना होता है। हम तो पानी के जैसे मिल गए थे। एमी पाजी बहुत सच्चे और प्यारे इंसान हैं। पंजाब के सुपरस्टार हैं। इनकी 27 से ज्यादा फिल्में आ चुकी हैं।

कैटरीना के सवाल पर बोले- पर्सनल न जाना

विक्की ने पत्रकारों के फिल्म से जुड़े सवालों के साथ ही अन्य बातों का भी खुलकर जवाब दिया, लेकिन जब कैटरीना से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बचने का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म बैड न्यूज के ट्रेलर का आखिरी डायलॉग है-पर्सनल न जाना, वही यहां बोल रहा हूं। इस सवाल का बस यही जवाब है। प्रमोशन के दौरान 12 साल के फैज ने विक्की से ऑटोग्राफ की डिमांड की। जो स्कूल ड्रेस में राजमंदिर में मौजूद था। इस पर विक्की ने फैज से उसकी उम्र पूछी, फैज ने जवाब में 12 साल बताई। तब विक्की ने कहा कि देखिए आज की जनरेशन को 12 साल की उम्र में कितनी बैबाकी से अपनी बात रखते हैं। हम इस उम्र में अपने पैरेंट्स के सामने बोल नहीं पाते थे। फिर फैज को उन्होंने स्टेज पर बुलाया और स्कूल के बैग से कॉपी निकालकर दी। उस पर ऑटोग्राफ दिए, फिर फोटो क्लिक करवाई। इस दौरान राजमंदिर के डायरेक्टर सौरभ सुराना ने विक्की और एमी को राजमंदिर के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मैनेजर अशोक तंवर, अंकुर खंडेलवाल और अनीश जैन मौजूद रहे।

कैटरीना के पोस्टर के साथ काम करने का मौका मिला

विक्की से जब फिल्म में कैटरीना के पोस्टर के साथ काम करने के एक्सपीरिएंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अब तक उनके साथ कोई फिल्म नहीं की है। जब मुझे उनके पोस्टर के साथ सीन करने का मौका मिला तो मैंने पूरी फिल्म का एक्सपीरिएंस लेने की ठान ली। वैसे तो मैं एक टेक पर ही काम करना पसंद करता हूं, लेकिन इस सीन पर मैंने 25 से ज्यादा टेक लिए। एमी से जब बॉलीवुड में उनके फ्यूचर पर पूछा गया तो उन्होंने कहा- जैसे-जैसे काम मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो बहुत आगे जाना है। मैंने पंजाब में बहुत सारी फिल्में की। वहां ज्यादातर कॉमेडी ही रही हैं। अब यहां बहुत कुछ अलग करने का भी मौका मिलेगा। सिंगल एलबम के सिंगर से सफर शुरू किया था। अब हॉलीवुड से रिटायरमेंट हो यही सपना है। मैं साल में एक या दो फिल्म पंजाबी में, जब समय और ऑफर मिलेगा तो बॉलीवुड में काम करता रहूंगा।

मेरे लिए लकी रही है पिंकसिटी

विक्की ने कहा कि जयपुर और राजमंदिर मेरे लिए बहुत लकी रहे हैं। मेरी फिल्म जरा हटके जरा बचके का गाना यहां रिलीज किया था। वह सुपर डुपर हिट रहा। इसके बाद मैंने कहा था कि मैं अपनी फिल्मों को जयपुर लेकर आऊंगा। फिर मैं सैम बहादुर के लिए आया। वह भी सुपरहिट रही। अब मेरी हैट्रिक होने वाली है, इसलिए मैं बैड न्यूज को भी यहां लेकर आया हूं।

एमी विर्क ने सुनाया गाना

राजमंदिर में फिल्म प्रमोशन के लिए आए सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने अपने हिट गाने दर्शकों के बीच सुनाए। दर्शकों ने एमी की जमकर तारीफ की। इसके बाद तौबा तौबा गाने पर विक्की ने जमकर डांस किया। जब स्क्रीन पर फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया तो विक्की स्टेज पर नीचे की तरफ की बैठ गए। दर्शकों का रिएक्शन देखने लगे। जब कैटरीना के पोस्टर वाला सीन आया तो दर्शकों के रेस्पॉन्स को देखकर वे बेहद उत्साहित नजर आए।

उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि पर स्टूडेंट्स का किया सम्मान

बेधड़क. जयपुर। महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल की ओर से दसवीं और बारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स का उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मान किया गया। यह समारोह एक खुशी का अवसर था, जिसने छात्रों और संकाय दोनों की कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी। समारोह की शुरुआत स्कूल प्रिंसिपल के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विभिन्न विषयों में असाधारण अंक हासिल करने वाले और अव्वल रहने वाले छात्रों को दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

बबीता, श्वेता और ईरम फातिमा को मॉडल ऑफ फेम खिताब

बेधड़क. जयपुर। फैशन और ग्लैमर के क्षेत्र में उभरती हुई मॉडल्स को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से पिंक कॉन्सेप्टस की ओर से मॉडल ऑफ फेम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। होटल सोवेनियर पिपरमिंट में हुए कन्वर्सेशन ओवर कॉफी सेशन के दौरान फैशन मॉडल बबीता मीणा, ईरम फातिमा और श्वेता किराड़ को मॉडल ऑफ फेम बाय पिंक कॉन्सेप्टस के टाइटल से नवाजा गया। फोर्टी विमन विंग की प्रेसिडेंट डॉ. अल्का गौड़, पिंक कॉन्सेप्टस के डायरेक्टर अमन वर्मा, फैशन डिजाइनर एवं एकेडमिशियन हर्षवर्धन सोनी, समाजसेवी योगेश खंडेलवाल, ज्वेलरी डिजाइनर इंद्रजीत दास, फैशन स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट सूबिया खान, इमेज मेकओवर एक्सपर्ट पूजा जैन मौजूद रही। अतिथियों ने तीनों मॉडल्स को क्राउन और शैश पहनाकर और फ्लॉवर बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बेटी फाउंडेशन की ओर से राहुल शर्मा, राज शर्मा, एडवोकेट शिव जोशी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

City इवेंट्स

हिंदू सेवा मंच की कार्यकारिणी घोषित

बेधड़क. जयपुर। हिंदू सेवा मंच के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने मंच की कार्यकारिणी घोषित की। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष प्रदीप खुराना एवं डॉ. संजीव सिंघल, महामंत्री राज कुलदीप सिंह व एसके भट्ट, संगठन मंत्री श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राम पुरुषवानी, प्रचार मंत्री प्रकाश मेडतवाल, मंत्री डीडी गर्ग, उपाध्यक्ष पूनम तिलक को बनाया गया है। कार्यकारिणी सदस्य सुधा शर्मा, चंचल चार्य, नीतू गैदर, जयप्रकाश खंडेलवाल, ज्योति यादव, अजय लुहाड़िया, नरेंद्र शर्मा, ताराचंद शर्मा, परितोष शर्मा, संत कुमार शर्मा और रमेश शर्मा को मनोनीत किया गया है।

भाटिया की पेंसिल स्केच प्रदर्शनी कल

बेधड़क. जयपुर। जवाहर कला केन्द्र में 12 से 14 जुलाई तक 76 वर्षीय कलाकार प्रताप कुमार भाटिया की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सुरेख दीर्घा में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होने वाली प्रदर्शनी में 150 से अधिक पेंसिल स्केच प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रताप कुमार भाटिया ने बताया कि उन्होंने कलात्मक ट्रेनिंग हासिल नहीं की है। उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने अपनी ऊर्जा को कला व समाज सेवा की ओर मोड़ा। कोरोना काल में जब बाहर जाने पर पाबंदी थी तो इन्होंने नकारात्मकता को दूर करने के लिए अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाला और पेंसिल स्केच बनाकर यह विराट संग्रह तैयार किया। प्रदर्शनी में कला प्रेमियों को सब्जियों, पशु-पक्षी, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पुरातत्व स्मारक, फेमस पर्सनैलिटी के स्केच शामिल हैं। प्रदर्शनी से पूर्व प्रताप कुमार भाटिया ने सिख धर्म के दस गुरुओं के पेंसिल स्केच बनाकर राजापार्क गुरुद्वारे में भेंट किए। कार्यक्रम में मालवीय नगर विधानसभा विधायक कालीचरण सर्राफ, सिक्किम हाईकोर्ट के रिटा. चीफ जस्टिस एनके जैन मुख्य अतिथि रहेंगे। एजुकेशनिस्ट पीडी सिंह और श्री कृष्णा रोलिंग मिल्स के डायरेक्टर विनोद गुप्ता विशिष्ट रहेंगे।

जेकेके में पंचतन्त्री बेला वादन आज

बेधड़क. जयपुर। जवाहर कला केन्द्र की ओर से मधुरम के अंतर्गत बेला वादन की प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार शाम 7:00 बजे रंगायन सभागार में पं. रविशंकर भट्ट की बेला वादन प्रस्तुति होगी। पं. रविशंकर भट्ट तैलंग विशेष पंचतन्त्री बेला का वादन करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही जयपुर के ध्रुवपदाचार्य पं. लक्ष्मण भट्ट तैलंग को पद्मश्री से नवाजा गया था। पं. लक्ष्मण भट्ट के स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र और शिष्य पं. रवि भट्ट तैलंग ने पद्मश्री ग्रहण किया था। पं. रवि भट्ट ने अपने गुरु की प्रेरणा से वायलिन में 5वां तार जोड़कर पंचतन्त्री बेला बनायी है। यह कार्यक्रम केन्द्र की ओर से जुलाई माह में चलने वाली शृंखला जुलाई झंकार का हिस्सा है। जुलाई झंकार में मानसून को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। गौरतलब है कि संगीत कार्यक्रमों की कड़ी में हाल ही केन्द्र की ओर से रामकुमार मालूणी व समूह के कलाकारों के लोक गायन की प्रस्तुति का आयोजन किया गया था।

14 को मोक्ष कल्याणक, 17 को मंदिर स्थापना दिवस

महामहोत्सव का पोस्टर मूल नायक भगवान नेमिनाथ के समक्ष अर्पित

बेधड़क | जयपुर

जनकपुरी-ज्योतिनगर में मुनि समत्व सागर ससंघ के पावन सानिध्य में तेरह से सत्रह जुलाई तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय महामहोत्सव के कार्यक्रम के फ्लैक्स, पोस्टर का विमोचन बुधवार को गायत्रीनगर मंदिर में किया गया।

मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष पदम जैन बिलाला ने बताया कि कार्यक्रम के पोस्टर को मंदिर जी में मूल नायक भगवान नेमिनाथ के समक्ष अर्पित कर मुनि संघ के सानिध्य में विमोचन किया गया। इस अवसर पर मंत्री देवेंद्र कासलीवाल, कोषाध्यक्ष सोभाग अजमेरा, सदस्य मिश्री लाल काला, महावीर बिंदायक्या, महिला मंडल अध्यक्ष शकुंतला बिन्दायक्या सहित जनकपुरी के ज्ञान चंद भोंच, राजेंद्र ठोलिया, इंद्र कुमार जैन, राजकुमार बाकलीवाल, मयूख कासलीवाल, नवीन पांड्या, दिलीप चांदवाड़, अंजू बाकलीवाल, विमला बिलाला, सोहनी देवी सौगानी आदि उपस्थित रहे। इस महामहोत्सव में कई धार्मिक आयोजनों के अलावा चौदह जुलाई को मूलनायक तीर्थंकर नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक, व सत्रह जुलाई को मंदिर का स्थापना दिवस रथ यात्रा के साथ मनाया जाएगा। विमोचन के अवसर पर कीर्ति नगर के महामंत्री जगदीश जैन, राज जैन सभा के महामंत्री मनीष बैद, मन्त्री विनोद कोटखावदा, युवा महा सभा के अध्यक्ष प्रदीप जैन लाला, सुभाष बज, बापूनगर के मनीष झंझरी आदि की गरिमामय उपस्थिति रही।

धर्म जागृति संस्थान देगा 24 नकद पुरस्कार

अहिंसक आहार शब्द को जन-जन तक पहुंचाने के लिए होगी प्रतियोगिता

बेधड़क | जयपुर

अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान प्रांत राजस्थान द्वारा आचार्य वसुनंदी के आशीर्वाद से आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय अहिंसक आहार पोस्टर प्रतियोगिता की बारह जुलाई अंतिम तिथि है।

प्रांतीय अध्यक्ष पदम जैन बिलाला ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550 वे निर्वाणोत्सव वर्ष को आचार्य वसुनंदी मुनिराज द्वारा अहिंसक आहार वर्ष घोषित किए जाने के क्रम में आयोजित की जा रही है, जिसमें 24 नकद पुरस्कार रखे गए हैं।

इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अहिंसक आहार शब्द को जन जन तक पहुंचाना है। इस के लिए पूरे राजस्थान में चालीस स्थानों पर स्थानीय संयोजक मनोनीत किए गए हैं, जो अहिंसक आहार का अपने स्तर पर जोर-शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। A3 साइज के पोस्टर्स में शाकाहार के विस्तृत स्वरूप अहिंसक आहार को दर्शाना है तथा पोस्टर्स घर से ही बनाकर स्थानीय संयोजक को अथवा संस्थान के जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय को भेजने हैं। इस पोस्टर प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर बनाने वाले 24 प्रतियोगियों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इससे न केवल अहिंसक आहार शब्द जन-जन तक पहुंचाने में मदद मलेगी, बल्कि प्रतियोगियों को भी मोटिवेशन मिलेगा।

उपलब्धि ट्रेवल प्लस लीजर ने अमेरिका में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए

उदयपुर दुनिया का दूसरा और एशिया का नंबर वन शहर

बेधड़क | जयपुर

राजस्थान के उदयपुर को पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, वहीं एशिया में यह शहर नंबर वन पर है। ट्रेवल प्लस लीजर ने अमेरिका में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए। ट्रेवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड के तहत दुनिया भर दस सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें मैक्सिको के शहर सैन मिगुएल डी ऑलेंडे को पहला स्थान उदयपुर को दूसरा स्थान व तीसेर स्थान पर जापान का क्योटो शहर है।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उदयपुर को वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरा स्थान व एशिया में पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि उदयपुर को दुनिया के सबसे खूबसूरत व सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान मिलना शहर की विरासत, कला-संस्कृति, खान-पान और स्थानीय लोगों का सम्मान हैं, जिन्होंने दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स की सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि राजस्थान दुनिया के सबसे पंसदीदा व बेस्ट पर्यटन स्थलों में शुमार है और यहां आने वाले पर्यटक सुखद यादें संजो कर अपने देश को लौटते हैं।

पर्यटकों की आवक बढ़ी

वहीं, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि इस साल की शुरूआत में ही प्रदेश में देशी व विदेशी पर्यटकों की आवक में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि राजस्थान पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है। पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि प्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों पर पर्यटकीय सुविधाओं को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित कर रहा है।

दुनिया के दस सर्वश्रेष्ठ शहर

1. सैन मिगुएल डी ऑलेंडे, मेक्सिको
2. उदयपुर, भारत
3. क्योटो, जापान
4. होई एन, वियतनाम
5. चियांग माई, थाईलैंड
6. फ्लोरेंस, इटली
7. बैंकॉक, थाईलैंड
8. टोक्यो, जापान
9. उबुद, इंडोनेशिया
10. फुंचाल, पुर्तगाल

नैतिकता के बिना धन, पानी के बिना कुएं के समान है।
विनायक शर्मा, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ, सच बेधड़क मीडिया ग्रुप

इजराइल का लगातार चौथे दिन हमला, शरणार्थियों को खान यूनिस खाली करने का अल्टीमेटम

गाजा के स्कूल पर एयरस्ट्राइक, 29 की मौत

एजेंसी | रफाह

इजराइल ने मंगलवार को फिर दक्षिणी गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक स्कूल पर हमला किया, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 29 पहुंच चुकी है। वहीं, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्कूल को विस्थापित फिलिस्तीनियों ने अपना आश्रय स्थल बनाया हुआ था। यह इजराइल का चार दिनों में किया गया लगातार चौथा हमला है।

हालांकि, इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। समें 29 लोगों की मौत हो गई। इजराइल पिछले 4 दिनों से ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जहां शरणार्थियों को रखा गया है। अब इजराइली सेना ने फिलिस्तीन लोगों को खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद वहां 3 बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा है।

संयुक्त राष्ट्र ने इसे खतरनाक कदम बताया है। साथ ही कहा है कि खान यूनिस से लोगों को निकालने के लिए और ज्यादा समय देने चाहिए। इस दौरान इजराइल शरणार्थियों पर हमला नहीं करे। इजराइली सेना ने बताया कि शनिवार से लेकर अब तक गाजा के स्कूलों पर तीन हमले किए गए हैं। शनिवार को इजराइली सेना ने यूएन के स्कूल पर एयरस्ट्राइक की थी। इजराइली सेना ने शनिवार को गाजा में एक स्कूल पर एयरस्ट्राइक की थी। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई और 75 से ज्यादा घायल हो गए थे। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कूल संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का था, जहां शरणार्थियों को रखा गया था।

स्कूल को घेर कर किया हमला

स्थानीय लोगों के मुताबिक इजराइली सेना ने पहले स्कूल को चारों ओर से घेरा और फिर उस पर हमला कर दिया। इजराइल के हमले से स्कूल की इमारत नीचे गिर गई, जिसमें रह रहे बच्चे दब गए। स्थानीय लोग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिसमें दो बच्चों को बचा लिया था, उसमें से एक बच्ची की हाथ में गंभीर चोट आई थी। वहीं दूसरे बच्चे के चेहरा और सिर पर कई चोट के निशान थे।

पहले स्कूल को बताया था सेफ जोन

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में ज्यादा बच्चे और महिलाएं थी। 50 घायलों का इलाज किया जा रहा है, बाकी लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया। वहीं इजराइली सेना ने स्कूल को आतंकवादियों का अड्डा बताया। हमले से बचने के सैकड़ों शरणार्थियों ने स्कूल की आस-पास की जगह को छोड़ दिया है। इससे पहले इजराइल ने स्कूल को सेफ जोन बताया था। पिछले महीने किए स्कूल पर हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे।

जंग में 38 हजार की मौत

इजराइल-हमास जंग के बीच पिछले 9 महीने से जंग जारी है। इसमें अब तक 38 हजार फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, इनमें 14,500 बच्चे शामिल हैं। वहीं गाजा के करीब 80% लोग बेघर हो गए। यह जंग अब मिस्र बॉर्डर के करीब गाजा के राफा शहर पहुंच गई है।

लोगों ने गाजा छोड़ राफा में ली थी शरण

दरअसल, जंग की शुरुआत में इजराइल की कार्रवाई से बचते हुए लोगों ने उत्तरी गाजा छोड़कर राफा में शरण ली थी। अलजजीरा के मुताबिक इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अब इजराइल की सेना यहां भी हमले की योजना बना रही है। इजराइल का तर्क है कि उन्होंने अब तक हमास की 24 बटालियन को खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी 4 बटालियन राफा में छिपी हुई हैं। इनके खात्मे के लिए राफा में ऑपरेशन चलाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की रेस्क्यू टीम के मुताबिक पिछले महीने भी इजराइली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाया था।

पुतिन से अच्छे संबंध का फायदा उठाए भारत: US

मोदी रुकवा सकते हैं जंग

एजेंसी | वाशिंगटन

पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका टकटकी लगाए बैठा रहा। अमेरिका ने यह तक कह दिया कि अगर कोई देश रूस से मिलता है तो उसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। इन सब के बाद अब अमेरिका का एक और रिएक्शन सामने आया है।

वाइट हाउस ने अपने एक बयान में मंगलवार को कहा है कि रूस के साथ भारत के संबंध अच्छी स्थिति में है, जिसका भारत को फायदा उठाना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि भारत चाहे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए कह सकता है।

यह बयान तब आया है जब पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत में है, युद्ध के मैदान में नहीं। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, वाइट हाउस की प्रेस सचिव करिन जीन-पियरे ने भारत को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार कहा है जिसके साथ वे स्पष्ट बातचीत करते हैं।

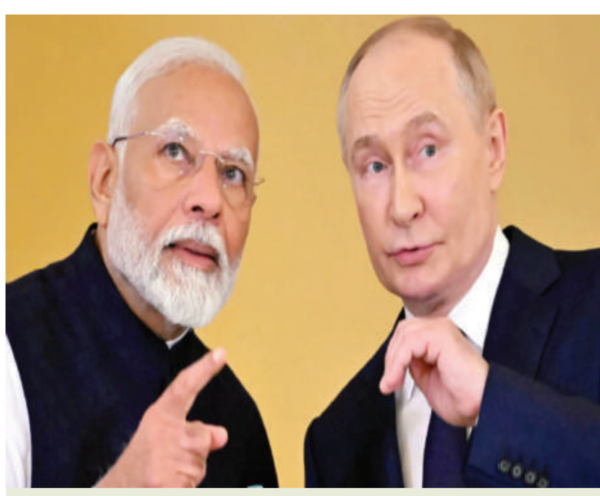

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था युद्ध में बच्चों की हत्या का मुद्दा

वाइट हाउस ने यह बयान तब दिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान युद्ध के दौरान बच्चों की हत्या का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति तब दुखी होता है जब जान जाती है। यह बयान हाल ही में कीव में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद आया है, जिसमें 37 बच्चे मारे गए थे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, "चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकी हमले हों - मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को जान जाने पर दुख होता है। लेकिन जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, जब हम मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तो यह दिल दहला देने वाला होता है। यह दर्द बहुत बड़ा है।"

यह बोलीं वाइट हाउस की प्रेस सचिव पियरे

पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर जीन-पियरे ने कहा, "भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, जिसमें रूस के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं और हमने इस बारे में पहले भी बात की है। इसलिए हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत सहित सभी देश यूक्रेन के मामले में शांति स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करें।" उन्होंने आगे कहा कि भारत चाहे तो यूक्रेन में युद्ध भी रुकवा सकता है। उन्होंने कहा, "हम यह भी मानते हैं कि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध उसे राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध करने की क्षमता देते हैं राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू किया, और वे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं।"

सच्चाई के साथ दिखी मौत

हथौड़ा समझा वो निकला मौत का सामान

एजेंसी | बीजिंग

चीन में एक बुजुर्ग महिला 20 साल पहले हथौड़ा समझकर जिसे जंगल से उठा लाई, उसकी सच्चाई जब मालूम हुई तो उसे सामने मौत दिख गई। रिपोर्ट के अनुसार महिला जिंदा हैंड ग्रेनेड से 20 साल से घर में लाल मिर्च कूट रही थी। यही नहीं घर की दीवारों पर कील ठोंकना और अखरोट तोड़ने से लेकर घर के कई कामों में वह उसका इस्तेमाल कर रही थी। महिला को यह कब और कैसे मालूम हुआ कि वह हथौड़ा नहीं हैंडग्रेनेड था? चलिए जानते हैं। घटना मिडिल चीन के हुबेई प्रांत के जियानगयांग की है।

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक महिला को इसका पता 23 जून को पता लगा, जब उसके पुराने घर की मरम्मत करने कुछ मजदूर पहुंचे। उन्होंने महिला के हाथ में यह हथियार देखा तो चौंक गए। उन्होंने उसे बताया कि यह हथौड़ा नहीं हैंडग्रेनेड है। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोकल पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत पहुंच हथियार जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा है "ग्रेनेड को जब्त करने के बाद, हमने एक्सपर्ट से इसे नष्ट करने के लिए कहा है।"

वह सामान्य वस्तु निकली हैंड ग्रेनेड

किन नाम की 90 वर्षीय महिला को 20 साल पहले हुआंगबाओ काउंटी में अपने खेत में काम करते समय एक असामान्य वस्तु दिखी। वह वस्तु धातु से बनी थी और काफी हद तक हथौड़े जैसे आकार की थी। वह उसे काम की वस्तु समझकर घर ले आई और घरेलू कामों में उसका इस्तेमाल करने लगी। किन को बीते 23 जून को मालूम हुआ कि वह जिसे हथौड़ा समझकर इस्तेमाल कर रही थी, वह असल में जिंदा हैंडग्रेनेड था।

दुबई में भारतीय युवक की बेरहमी से हत्या

एजेंसी | दुबई

दुबई में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा अटैक किए जाने के बाद पंजाब के एक व्यक्ति की मौत हो गई।

रिपोर्टों के अनुसार यह दुखद घटना कुछ दिन पहले हुई थी और मृतक के परिवार को अब उनके शव के घर पहुंचने का इंतजार है। 21 वर्षीय मृतक पंजाब के लुधियाना जिले का है। रायकोट उप-विभाग के अंतर्गत लोहटबद्दी गांव के मनजोत सिंह के रूप में पहचाने गए व्यक्ति का शव शुक्रवार तक घर पहुंचने की उम्मीद है। मनजोत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसके पिता दिलबाग सिंह एक मजदूर हैं। उन्होंने परिवार के लिए आजीविका कमाने के वास्ते अपने बेटे को दुबई भेजा था।

मीडिया से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि उनका बेटा करीब एक साल पहले दुबई गया था, जहां वह एक दवा कंपनी में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि दुबई में काम करने वाले पुरुषों के दो समूहों के बीच झड़प के बाद उनके बेटे की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि यह घटना कथित तौर पर 21 जून को हुई थी, लेकिन उन्हें उसकी मौत के बारे में कई दिनों बाद पता चला।

सृष्टिविनायक एंटरटेनमेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक मिताली यादव द्वारा सच बेधड़क दैनिक हिन्दी अखबार, 34/16-ए, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान) से प्रकाशित एवं भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, रेलवे क्रॉसिंग टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान) से मुद्रित।
संपादक: विनायक शर्मा*, **फोन नं. :** 9664014179 (ऑफिस), **ई-मेल:** news@sachbedhadak.com, **RNI No. :** RAJHIN/2021/82557 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

दैनिक हिन्दी अख़बार
सच बेधड़क

"सच बेधड़क" दैनिक हिन्दी अख़बार की प्रति PDF के माध्यम से मुफ़्त प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर Click कीजिए

Telegram

https://rb.gy/3bkrnl